04 - रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा...

05 - ईरान की जंग के बीच उनके सिनेमा पर एक नजर

A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 8 अप्रैल, 2026

06 - हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतू परमार पहुंची नगरपालिका

07 - कोई भी प्रभावित किसान फसल सर्वे में न छूटे, क्षति की रिपोर्ट...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 215, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

युद्ध और इसराइल : गांधी और आइंस्टीन की नजर में

अरुण कुमार त्रिपाठी/रणधीर गौतम

पिछले महीने ब्रिटेन की मशहूर पत्रिका 'द इकानमिस्ट' की संपादक जैनी मिल्टन बेडोज़ के एक इंटरव्यू पर काफी विवाद हुआ। वे अमेरिकी पोडकास्टर टकर कार्लसन से पूछ रही थीं कि क्या वे यह मानते हैं कि इजराइल को राजनीतिक रूप से अपना अस्तित्व कायम रखने का अधिकार है? क्या ऐसा मानने से वे यहूदीवादी नहीं हो जाएंगे? कार्लसन ने यह कहकर बात को खत्म किया कि वे किसी भी देश का सर्वनाश नहीं चाहते। लेकिन मुश्किल यही है कि यूरोप, अमेरिका और भारत तक के मीडिया में गाज़ा पर हुए इजराइली हमले से लेकर ईरान पर अमेरिका के साथ किए गए हमले में भी इसी प्रकार के पूर्वाग्रह वाले सवाल पूछे जा रहे हैं।

तमाम पत्रकार यही पूछ रहे हैं और लिख रहे हैं कि अगर ईरान को नष्ट नहीं किया गया तो क्या इजराइल या अरब देश बच पाएंगे? यह आख्यान भी चलाया जा रहा है कि अगर ईरान शक्तिशाली बना रहा तो वह क्या सऊदी अरब स्थित मक्का-मदीना पर कब्जा नहीं कर लेगा। क्या हजारों साल पुराने देश ईरान को इस धरती पर अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम करने का हक है? क्या फिलिस्तीन को अपने अस्तित्व का अधिकार है? लेकिन जब साम्राज्यवाद सवाल पूछने के तरीकों को बदल देता है तो ऐसे ही विकृत सवाल पूछे जाते हैं कि क्या इजराइल को जीने का हक नहीं है? दरअसल इस सवाल के माध्यम से एक ओर फिलिस्तीन के सवाल को ही लोगों की स्मृति से गायब कर दिया गया है और अब ईरान के दीर्घकालिक इतिहास और सभ्यता के रूप में उसके अस्तित्व को भी मिटाने की कोशिशें चल रही हैं। कई पत्रकार तो यह आख्यान भी चला रहे हैं जल्दी ही हार्मुज जलडमरूमध्य का नाम ट्रंप स्ट्रेट होने वाला है।

महात्मा गांधी यहूदियों के साथ पूरी सहानुभूति जताते हुए फिलस्तीन पर उन्हें थोपे जाने को अनुचित मानते हैं। वे जुलाई 1946 में हरिजन में लिखते हैं- 'मैं अब तक यहूदी-अरब विवाद पर कुछ कहने से बचता रहा हूं। लेकिन मेरी नजर में उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से और अब आतंकवाद का नग्न रूप में सहारा लेकर फिलस्तीन पर अपने को थोप कर गलती की है। वे जिस प्रकार के विश्व नागरिक रहे हैं, उस लिहाज से वे किसी भी देश के सम्माननीय अतिथि हो सकते थे। उनकी मितव्ययिता, प्रतिभा और उद्यमशीलता के कारण सभी जगहों पर उनका स्वागत होता। ईसाइयों के जगत पर यह एक कलंक है कि न्यू टेस्टामेंट (नई गवाही) के गलत पाठ के कारण उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ।' वे कहते हैं 'अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो पूरे यहूदी समुदाय को इसका दोष दिया जाता है।'

अगर आइंस्टीन जैसा कोई यहूदी कोई महान आविष्कार करता है या कोई असाधारण संगीत तैयार करता है तो उसका श्रेय उस आविष्कर्ता को ही जाता है न कि पूरे समुदाय को। उनकी जो अवांछनीय दुर्दशा हुई है, उसके लिए यहूदियों के प्रति मेरी सहानुभूति है। लेकिन कोई सोच सकता है कि प्रतिकूल स्थितियों के कारण उन्होंने शांति का पाठ सीखा होगा। ऐसे में वे अमेरिकी धन और ब्रिटिश सेना के सहारे क्यों एक बेगानी धरती पर अपने को थोप रहे हैं? फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के काम को टिकाऊ बनाने के लिए वे आतंकवाद का सहारा क्यों ले रहे हैं? अगर वे अहिंसा के बेजोड़ हथियार का सहारा लेते जिसे कि उनके पैगंबरों ने सिखाया है और जीसस जो कि स्वयं यहूदी थे और जिन्होंने पाप से कराहती दुनिया का दुख दूर करने के लिए कांटों का ताज खुशी-खुशी पहन लिया, तो यह विकल्प श्रेष्ठ और गौरवशाली होता।'

गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को अपना आदर्श बताने वाले महान वैज्ञानिक और यहूदी अल्बर्ट आइंस्टीन की उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वे अपने हृदय से गांधी के बेहद करीब थे। वे यहूदियों के समर्थक थे, लेकिन जब 1952 में आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनाए जाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने मना कर दिया। वास्तव में उनके सोच की दिशा न तो आतंकवाद की ओर थी और न ही युद्ध की ओर। वे शांति संबंधी तमाम वैश्विक प्रस्तावों के समर्थक थे और समर्थक थे संयुक्त राष्ट्र, विश्व सरकार और एटमी निरस्त्रीकरण और नागरिक अधिकारों के।

18 अप्रैल 1955 को जब अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मेज पर 14 मई को पढ़ने वाले 'इजराइल दिवस' के लिए एक संदेश पड़ा था। उस में लिखा था, 'मैं आप से न तो एक अमेरिकी नागरिक के रूप में बात कर रहा हूं और न ही एक यहूदी के तौर पर। मैं आप से एक ऐसे मानव के रूप में बात कर रहा हूं जो कि अधिक गंभीरता के साथ चीजों को वस्तुनिष्ठ रूप में देखना चाहता है। अपनी इस कमजोर क्षमता के बावजूद मैं जिस मकसद के लिए काम करना चाहता हूं वह है शांति और न्याय। भले कोई इससे नाराज हो या खुश।'

यह विडंबना है कि जिस यहूदी समुदाय और इजराइल के लिए आइंस्टीन भरपूर सहानुभूति रखते थे और हिब्रू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए जिन्होंने चंदा जमा किया वह इजराइल आज आइंस्टीन के शांतिवाद को ही आग लगा रहा है। वे लिखते हैं, 'युद्ध कोई खेल नहीं है। हमारी लड़ाई युद्ध के विरुद्ध ही होनी चाहिए। जन समुदाय शांति के समय ऐसा संगठन बनाकर युद्ध की संस्था से लड़ सकता है जो सैन्य सेवा से पूरी तरह इंकार कर दे। (4 जनवरी 1928 वूमेन इंटरनेशनल लीग फार पीस को संदेश)। आइंस्टीन कहते हैं, 'मेरे लिए किसी मनुष्य को मारना हत्या है। वह तब भी हत्या है, जब वह बड़े पैमाने पर राज्य की नीति के तहत किया जाए।' वे युद्ध रोकने के दावे और युद्ध की तैयारी करते जाने के पाखंड पर टिप्पणी करते हुए कहते थे कि आप युद्ध की तैयारी करते हुए युद्ध नहीं रोक सकते।

आइंस्टीन मानते थे कि उनका युद्ध विरोध तार्किकता से अधिक भावना पर आधारित है। जबकि गांधी के युद्ध विरोध को हम ठोस रणनीति और तार्किक आधार पर देख सकते हैं। गांधी का कहना है कि युद्ध रोकने के लिए सारे प्रयास तब तक व्यर्थ जाएंगे जब तक युद्ध के कारणों को समझा नहीं जाता और उनसे मौलिक रूप से निपटा नहीं जाता। आज पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध और उसके प्रभावों में हो रही तबाही और आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए बीसवीं सदी की यह दो महान विभूतियों के संदेशों पर विचार करना हमारी सभ्यता की आवश्यकता है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

हुल्लड़ों को इंकलाब
किस तरह कहें
हम दिये को आफताब
किस तरह कहें।
नूर है उसका उधार,
दाग बेशुमार
आपको हम माहताब
किस तरह कहें।
होश जो वापस हमें
लौटा नहीं सके
फिर भला उसको
शराब किस तरह कहें।
जंग भी लाजिम रही है
अम्न के लिए
पर तबाही का हिसाब
किस तरह कहें।
शय सभी बेमिस्ल हैं
इस क़ायनात मे
एक ही को लाजवाब
किस तरह कहें।

– दिनेश मालवीय 'अश्क'

समाज जैसा बनेगा वैसा ही देश बनेगा

संत मलूक दास की 452वीं जयंती के कार्यक्रम में बोले संघ चीफ मोहन भागवत

कहा-संत भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए काम करें, वृंदावन में संत के पैर छुए

मथुरा (एजेंसी)। संत मलूक दास की मंगलवार को 452वीं जयंती थी। वृंदावन के मलूक पीठ में उनका जन्मोत्सव

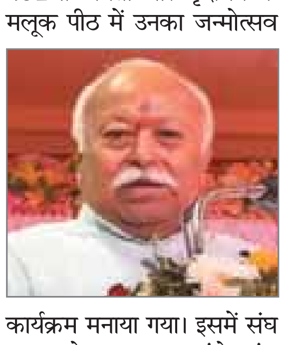

कार्यक्रम मनाया गया। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। मंच पर संत रसिक माधव दास ने मोहन भागवत को शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। भागवत ने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। संघ प्रमुख ने कहा- समाज को गो-भक्त बनाया जाए, तो गो-हत्या अपने आप रुक जाएगी। जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके मन में भी यह बात है। वे करना चाहते हैं, लेकिन कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। ऐसे में साहसी कदम उठाने के लिए समाज का साथ जरूरी है। गो-जागृति को मजबूत करना होगा। जब जनभावना तैयार हो जाएगी, तो व्यवस्था को भी उसे मानना पड़ेगा। भारत की यही सामूहिक इच्छा बन जाएगी।

संघ प्रमुख ने सूर्य से जुड़ा हुआ किस्सा सुनाया

संघ प्रमुख ने कहा– सूरज (सूर्य) ने सोचा कि छुट्टी पर जाएंगे। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया और कहा– भाई, मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। मेरा चार्ज कौन लेगा लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक दीप खड़ा हुआ और बोला– मुझे नहीं पता कि मैं आपका चार्ज ले सकता हूं या नहीं। लेकिन जब तक मेरा तेल और बाती कायम है, तब तक मैं जलता रहूंगा।

एअर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन का इस्तीफा

नई दिल्ली (एजेंसी)। एअर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफीसर कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एयर इंडिया ने नए सीईओ की तलाश भी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, विल्सन सितंबर में

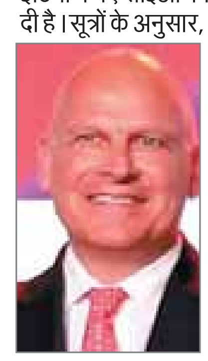

अपना पद छोड़ सकते हैं। पिछले हफ्ते हुई कंपनी की बोर्ड बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। विल्सन को 2022 में एअर इंडिया का सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 सालों के लिए, जुलाई 2027 तक था। रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरलाइन अहमदाबाद प्लेन क्रैश की फाइनल जांच रिपोर्ट आने के बाद नए सीईओ की नियुक्ति करेगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) ने 12 जुलाई 2025 को हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की थी।

बंगाल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बुरा होगा

- **रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिलाई 1971 की याद**

कोलकाता (एजेंसी)। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर तगड़ी लताड़ लगाई है। इस बार इसकी वजह पाकिस्तान की ओर से बीते दिनों आई गीदड़भभकी है। बीते दिनों पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने

भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कोलकाता तक घुसकर हमला करने की बात कही थी, जिसके बाद अब राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई है। रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को 55 साल पहले की वह घटना भूलनी नहीं चाहिए जब उसने बंगाल पर आंख उठाने की जुर्रत की थी तब कैसे वह दो टुकड़ों में बंट गया था।

- **ख्वाजा आसिफ ने दी थी गीदड़भभकी**– इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीते शनिवार को भारत को गीदड़भभकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुस्साहस की कोशिश का जवाब कोलकाता में हमले से दिया जाएगा। आसिफ ने अपने होमटाउन सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए एक बयान में कहा था, अगर भारत इस बार हमें जिम्मेदार ठहरा कर कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, तो हम कोलकाता तक निशाना साधेंगे। अब राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को समझा दिया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना की स्वीकृति

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार ने फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफटीआरआई) खोलने को मंजूरी दे दी है। मोहन यादव कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यह इंस्टीट्यूट प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन पर रिसर्च और बजट आकलन समेत

उज्जैन एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ मंजूर, नौ अप्रैल से होगी गेहूं की खरीद, अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेंगे 10000 रुपए

अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए काम करेगा। इसका संचालन शुरुआत में प्रशासन अकादमी से किया जाएगा। इसके अलावा एससी वर्ग के छात्रों के लिए दस हजार रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप भी मंजूर की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण की दिशा में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश की प्रगति को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों और

सिंहस्थ-2028 के कार्यों के लिए डेडलाइन तय, सीएम ने कहा- 2027 की दीपावली तक सभी काम पूरे हों

महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए कुल 16,720 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस बैठक में शिक्षा, कृषि, सिंचाई, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार ,भोपाल में एक अत्याधुनिक वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा। किसानों के हित में आगामी 3 वर्षों के लिए चना एवं मसूर के उपार्जन के लिये 3,174 करोड़ रुपये और मंदसौर की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देते हुए आर.टी.ई. के तहत फीस प्रतिपूर्ति, पीएमश्री स्कूल योजना के विस्तार और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गयी। साथ ही, उज्जैन हवाई पट्टी को एयरबस विमानों के अनुकूल विकसित करने और दिल्ली में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को 10 हजार रुपये मासिक सहायता देने जैसे दूरगामी फैसले भी लिए गए हैं। यह निर्णय प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुँचाने के सरकार के संकल्प को दर्शाते हैं। सिंहस्थ-2028 के कार्यों के लिए डेडलाइन तय, सीएम मोहन यादव ने कहा- 2027 की दीपावली तक सभी काम पूरे हों।

कातन सिंचाई परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि बैठक में मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से जुड़ी कातन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में 3500 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा और 120 गांवों के 1358 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

25 प्रतिशत चना, 100 फीसदी मसूर खरीदेगी सरकार

कैबिनेट ने चना और मसूर की खरीदी को भी मंजूरी दी है। चने का भाव 5000 रुपए और मसूर का 5800 रुपए क्विंटल है। सरकार चने के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत खरीदी करेगी और मसूर का 100 फीसदी खरीदी करने का फैसला किया गया है। इसके लिए 3174 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

परंपरा पर आधारित नियम, भेदभाव पर नहीं

- **सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर एससी में बोली केंद्र सरकार**

भगवान अयप्पा के 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' स्वरूप के कारण है यह रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरलम में मौजूद सबरीमाला मंदिर को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात रखी। केंद्र सरकार ने कहा कि पूजा की जगह में कौन जा सकता है, यह लिंग भेदभाव का मामला नहीं है, बल्कि यह धार्मिक रीति-रिवाजों, मान्यताओं और देवता के खास स्वरूप पर आधारित है।

इसके साथ ही सुनवाई से पहले दायर अपने लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि सबरीमाला में महिलाओं (10-50 वर्ष की उम्र के बीच) पर लगा प्रतिबंध भगवान अयप्पा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप के कारण

है, न कि किसी अपवित्रता या हीनता की भावना के कारण।

किसी प्रथा की समीक्षा करना संवैधानिक समीक्षा नहीं

केंद्र ने कहा कि इस तरह की कवायद का मतलब यह होगा कि अदालतें किसी धर्म की आंतरिक समझ की जगह अपने खुद के दार्शनिक विचारों को थोप रही हैं। इसके अलावा केंद्र ने कहा कि, यह जांच करना कि कोई प्रथा तर्कसंगत है, न्यायिक संवेदनाओं के अनुरूप है या परिवर्तनकारी संवैधानिक सिद्धांतों के साथ मेल खाती है, संवैधानिक समीक्षा नहीं हैं। न्यायाधीश न तो धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षित हैं और न ही उनके पास ऐसे संस्थागत साधन हैं जिनसे वे धार्मिक सवालों पर फैसला दे सकें।

असम पुलिस की दबिश, नहीं मिले पवन खेड़ा

हिमंत बोले-पाताल से भी ढूंढकर लाएंगे, कांग्रेस ने की आलोचना

गुवाहाटी/नई दिल्ली (एजेंसी)। असम पुलिस मंगलवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में असम पुलिस ने पवन खेड़ा के घर छानबीन भी की। इस दौरान पवन खेड़ा घर में मौजूद नहीं थे। इससे असम के साथ दिल्ली की

सियासत भी गरमा गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा घबरा गए हैं, इसलिए पुलिस भेजकर डराने की कोशिश कर रही है। इस बीच सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्हें असम पुलिस के ऐक्शन की जानकारी नहीं है।

रिंकी भुइंया सरमा के ऊपर लगाए थे आरोप

बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि असम के सीएम की पत्नी रिंकी भुइंया सरमा के पास तीन विदेशी पासपोर्ट हैं और उनके नाम से कई कंपनियां विदेशों में रजिस्टर्ड है। उनके खिलाफ रिंकी भुइंया ने असम पुलिस से शिकायत की गई थी। असम पुलिस के एसीपी देबोजित नाथ ने बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी के पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 8 अप्रैल 2026

> जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
>
> चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

अब तय सीमा से ज्यादा क्षेत्र में हो सकेगी दुर्लभ खनिजों की खोज

- संशोधनों की अधिसूचना जारी, केंद्र ने खनन नियमों में किए संशोधन

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सोमवार को दुर्लभ खनिजों के खनन से जुड़े नियमों में संशोधनों की अधिसूचना जारी कर दी। संशोधित नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर तय सीमा से अधिक क्षेत्र में दुर्लभ खनिजों की खोज कर सकेंगे। इससे गहरे क्षेत्रों से खनिजों को निकालने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संशोधनों के तहत खनन पट्टों और समग्र लाइसेंसों में सटे हुए क्षेत्रों को खनन में शामिल

करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रमुख पट्टों में संबंधित खनिजों को जोड़ने की भी अनुमति होगी। सटे हुए क्षेत्रों को शामिल करने से गहराई में स्थित खनिजों का ज्यादा से ज्यादा खनन बढ़ेगा, जिनकी अलग से खोज आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त आपरेटर मौजूदा पट्टे के क्षेत्र का 10 प्रतिशत या लाइसेंस क्षेत्र का 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त क्षेत्र में खनिजों की खोज कर सकेगा। नीलामी वाले पट्टों के लिए ऑपरेटर को जोड़े गए भूमि से खनिजों पर नीलामी प्रीमियम का 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा, जबकि गैर-नीलामी पट्टों के धारकों को ऐसे उत्पादन पर रायल्टी के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। संशोधनों के तहत खनन पट्टे में किसी भी अन्य खनिज को शामिल करने की अनुमति दी गई है।

देश के मुसलमानों को भड़का रही है कांग्रेस

- खरगे के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से करने पर अब बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए इसे जिहादी पार्टी बताया है। साथ ही चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, बल्कि ये इंडियन जिहादी

कांग्रेस बन चुकी है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खगरे मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें सीधे-सीधे भड़का रहे हैं। कि बीजेपी-आरएसएस एक जहरीला सांप है। ये जहां दिखे मार दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, ये पहली बार नहीं है और न ही ये संयोग से दिया हुआ बयान है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अपने राजनीतिक विरोधियों शुद्ध रूप से हत्या करवाने का बयान है। शहजाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, खरगे ने पहले भी बीजेपी-आरएसएस और पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास किया है।

विधानसभा मां की तरह, हम अपने दायित्व को समझें

भोपाल। विधानसभा के बारे में जब हम विचार करते हैं तो तरह-तरह के विचार आते हैं। अगर सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है तो पंचायत व नगरीय निकाय छोटी इकाई हैं। विधानसभा पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा की भूमिका मां की तरह होती है। जिस तरह मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उसका लालन-पालन कर उसे देश के हित में तैयार करने की कल्पना करती है, ठीस उसी तरह हम भी विधानसभा को मां की भूमिका में देखेंगे तो हम भी अपने दायित्व को उसके संपूर्ण रूप में देख पाएंगे। अपनी भूमिका के बारे में सोच पाएंगे। यदि मां विधानसभा के सदस्य के रूप में हम सभी के विचार में प्रदेश की आठ करोड़ जनता के कल्याण का ख्याल नहीं आता है तो हमारी भूमिका अधूरी है। हमें इस अधूरी भूमिका को पूर्ण करने का कार्य करना चाहिए।

यह बात विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए नवगठित सभा समितियों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा तथा नेता प्रतिपक्ष उमंग

सिंघार उपस्थिति थे।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश के विधायी इतिहास में विधानसभा की समितियों ने उल्लेखनीय कार्य किया है। मगर बीते कुछ वर्षों में कुछ सदस्य लगातार इन समितियों की बैठकों में अनुपस्थित रहे। इस पर चिंतन की आवश्यकता बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि समितियों की बैठक नियमित होने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। एक वर्ष में कम से कम 12 बैठकें होने की अपेक्षा है। समिति की बैठक होने से विधानसभा के कार्य व्यवहार में सुधार की संभावना होगी। समितियों की बैठक का यदि परिणाम नहीं भी निकलता है तो भी अध्ययन प्रक्रिया से हमारा ज्ञान समृद्ध होगा।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संसदीय परंपरा के पालन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने विधानसभा में कुछ सदस्यों के आचरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई बार कुछ सदस्य दायरे के बाहर जा कर कार्य कर जाते हैं। सकारात्मक आलोचना का स्वागत है लेकिन इस तरह का आचरण अपेक्षित नहीं होता। ऐसे में संसदीय समितियों का बड़ा महत्व है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय ज्ञान व नवाचारों के माध्यम से मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाहियां संसदीय इतिहास की परंपरा को समृद्ध करेंगी।

संदीप राशिनकर हुए मुंबई में सम्मानित

इंदौर। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और संस्कृति मंत्री आशीष शेलार और ठाणे की महापौर शर्मिला पिंपळोलकर ने शहर के चित्रकार संदीप राशिनकर को कल मुंबई में सम्मानित किया।

दादर के पु. ल. देशपांडे कला अकादमी में स्वामीराज प्रकाशन द्वारा आयोजित प्रशांत डिंगणकर की कृती मनबाधा के भव्य लोकार्पण प्रसंग पर यह सम्मान उनके आवरण कला अवदान के लिए किया गया। ज्ञातव्य है कि साहित्य अकादमी दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रभात प्रकाशन सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशनों के लिए संदीप अब तक सैकड़ों कलाकृतियों का आवरण बना कर इस क्षेत्र में

चर्चित हो चुके है। आवरण कला में उनके नवाचार, अभिनवता और अर्थवत्ता ने उन्हें देशभर में एक विशेष पहचान दी है। इस सम्मान के प्रसंग पर मंच पर मराठी के ख्यात लेखक डॉ. महेश केलुसकर, प्रवीण दवणे, ग़ज़ल नवाज़ भीमराव पांचाळे, रजनीश राणे मौजूद थे। डॉ. नरेंद्र पाठक, हास्य कवि अशोक नायगांवकर, राजेंद्र चव्हाण सहित अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में यह गरिमामय कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

अब किराने की दुकान पर भी मिलेगा 5 केजी वाला सिलेंडर

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5 केजी वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों का डेली एलोकेशन (यानी एक दिन की लिमिट) दोगुना कर दिया है। बढ़ा हुआ कोटा खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए रिजर्व रहेगा। ये छोटे सिलेंडर किराने की दुकान और पेट्रोल पंप से खरीदे जा सकेंगे। सरकार ने

2-3 मार्च की औसत सेल के आधार पर 5 केजी वाले एलपीजी सिलेंडर की एक्स्ट्रा सप्लाई देने का फैसला किया है, जो पहले से तय 20 फीसदी की लिमिट से अलग होगी। अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसलिए प्रवासी मजदूरों और कम आय वाले वर्ग को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है।

16 साल बाद पकड़ा गया लश्कर का खतरनाक आंतकी अबू हुरैरा

- कश्मीर में बड़ी सफलता, चार अन्य को भी दबोचा

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले का एक साल पूरा होने से पहले लश्कर ए तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतर-राज्यीय इस मॉड्यूल में कुल पांच लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें 16 साल से चकमा देर रहा लश्कर को कुख्यात आतंकी अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा भी शामिल है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार यह कफी समय से पकड़ से बच रहा था। बताया जा रहा है कि आतंकी का संपर्क कई नेटवर्क के साथ है। गौरतलब हो कि पिछले साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में 27 पर्यटकों को मारकर पूरे देश को झकझोर दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है।

पांच में से तीन श्रीनगर के रहने वाले

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में श्रीनगर के तीन निवासी शामिल हैं जिसमे मोहम्मद नकीब भट, आदिल राशिद भट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा है। जिन पर आतंकियों को पनाह देने, खाना खिलाने और अन्य तरह की मदद करने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि एक विदेशी आतंकी, राज्यों में सक्रिय लश्कर नेटवर्क की मदद से, जाली दस्तावेजों और फर्जी पहचान का इस्तेमाल करते थे।

25 युवक-युवतियों ने चुने अपने हम सफर, मंच पर बोले बिंदास

गांधी हॉल में उमड़ा क्षत्रिय खंगार राजपूत समाज, इंदौर का अखिल भारतीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन संपन्न

इंदौर। शहर के ऐतिहासिक गांधी हॉल में रविवार को क्षत्रिय खंगार राजपूत समाज इंदौर के तत्वावधान में निःशुल्क अखिल भारतीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन में 500 से अधिक प्रविष्टि प्राप्त हुई थीं। इनमें से अधिकांश युवक-युवतियों ने मंच पर जाकर अपना परिचय दिया और उन्हें कैसा जीवन साथी चाहिए। विचार साझा किए। इस सम्मेलन में 25 युवक-युवतियों ने अपने हमसफर का चुनाव किया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए समाज जनों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षत्रिय खंगार विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार (नन्नाजी) रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि कप्तान सिंह सहसारी, सन्मुख, अमित परिहार (प्रदेश अध्यक्ष, विकास संघ), राजू ठाकुर (अध्यक्ष, क्षत्रिय खंगार समाज, उज्जैन) विधायक गोलू शुक्ला, महेन्द्र हार्डिया, भाजपा नेत्री सविता अखंड, पूर्व नपा अध्यक्ष नीतू राय थी। कार्यक्रम का संयोजन इंदौर क्षत्रिय खंगार समाज के अध्यक्ष विजयसिंह तोमर, सचिव गोपालसिंह कनेरिया सहित समाज के वरिष्ठ दौलतराम कनेरिया, पूर्व अध्यक्ष दुर्पाल सिंह, श्याम धनोतिया, यशवंत शिवरे, राजेन्द्र शिवरे, बीड़ी ठाकुर, मनोज ठाकुर, संजयसिंह पंवार, कमल

मगरे, राजेश धनोतिया, सन्नी शिवरे सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने किया। इस अवसर पर समाज की प्रतिभाओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम से पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। इसमें लोक गीतों का समावेश रहा।

देशभर से आए 200 से अधिक जिलों के प्रतिनिधि- सम्मेलन में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे विभिन्न राज्यों के लगभग 200 से अधिक जिलों से वरिष्ठ समाज बंधु और युवक-युवतियां अपने परिवारों के साथ उपस्थित हुए।

प्रतिभाओं का संगम- मंच से परिचय देने वाले युवक-युवतियों में उच्च शिक्षित वर्ग की प्रधानता रही, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, व्यापारी और वकील जैसे डिग्री धारक शामिल थे। सभी ने उत्साहपूर्वक अपना परिचय देकर जीवनसाथी के चयन की दिशा में कदम बढ़ाया।

सफल संचालन- कार्यक्रम का कुशल संचालन क्षत्रिय खंगार राजपूत समाज, इन्दौर के अध्यक्ष डॉ. विजयसिंह तोमर, जीवन कनेरिया द्वारा किया गया। उन्होंने समाज की एकता और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए ऐसे आयोजनों की महत्ता पर जोर दिया।

6 ने लांघ दी कूनो की सीमा

खुले जंगल में घूम रहे 12 चीते

खौफ में एमपी-राजस्थान के किसान, दूर तक सुनाई दे रही गूंज

श्योपुर (एजेंसी)। भारत के चीता प्रोजेक्ट ने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई है, जिसकी गूंज अब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के जंगलों तक सुनाई दे रही है। कूनो के 12 चीते अब पूरी तरह फ्री-रेंज यानी खुले जंगल में घूम रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से आधे यानी 6 चीते पार्क की हदें पार कर ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और राजस्थान के बारां जिले तक पहुंच चुके हैं।

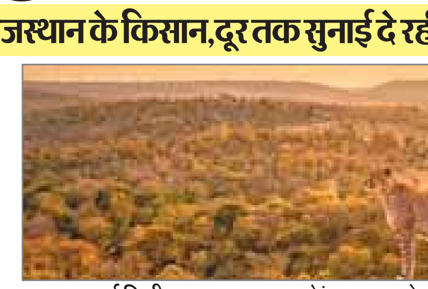

17,000 वर्ग किमी का नया साम्राज्य- केंद्र सरकार ने चीतों के कुनबे को बसाने के लिए 17,000 वर्ग किमी का एक विशाल चीता लैंडस्केप नोटिफाई किया है। यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश के 12 और राजस्थान के 13 जिलों को आपस में जोड़ता है। इस मास्टर प्लान का मकसद कूनो, गांधी सागर अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स रिजर्व के बीच चीतों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करना है।

आमने-सामने आए इंसान और चीते

चीतों का कूनो से बाहर निकलना उनकी सफलता का प्रतीक तो है, लेकिन यह मानव-वन्यजीव संघर्ष की नई चुनौती भी लाया है। हाल ही में सबलगढ़ से एक वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक ग्रामीण अपनी भैंस को चीते से बचाने के लिए उसे खदेड़ता नजर आया। रिहाइशी इलाकों के पास चीतों की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह उनकी प्राकृतिक बसावट का हिस्सा है। कूनो प्रोजेक्ट का यह दूसरा चरण सबसे कठिन है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आए इन मेहमानों के लिए अब अस्तित्व की परीक्षा है। 2022 से अब तक कई मौतों और चुनौतियों के बाद, 12 चीतों का खुले में घूमना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 25 जिलों के ग्रामीणों को इसके लिए तैयार करना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

पंजाब में नवजोत की पत्नी नवजोत का नया सियासी दांव

9 साल पुरानी पार्टी का पोस्टर शेयर कर बढ़ाई हलचल, कांग्रेस छोड़ चुकीं

अमृतसर (एजेंसी)। पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस के पूर्व पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने अब नया दांव खेला है। उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर नई दिल्ली की 9 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का पोस्टर शेयर किया है। कयास लगाया जा रहा कि वह अब इसी पार्टी का झंडा उठाकर पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई की उन्होंने इस पार्टी को जॉइन कर लिया।

लेकिन इससे अब उनके बीजेपी में जाने अटकलों पर रोक

लग गई है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा- हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प का काम किया है, जिसमें हमने वर्तमान राजनीतिक नेताओं के प्रदर्शन मानकों का गहराई से अध्ययन और मूल्यांकन किया है। हम केवल अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं और लोगों को वही देना चाहते हैं, जिसके वे वास्तव में हकदार हैं और हमसे अपेक्षा रखते हैं। नवजोत कौर ने पार्टी की घोषणा के लिए की गई पोस्ट में ये लिखा-एक जैसी सोच के लोगों को जोड़ा- नवजोत कौर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह एक दिव्य प्रेरणा है, जिसने कुछ समान सोच वाले लोगों को एक साथ जोड़ा है, जिनमें क्षमता, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प है कि वे हर राज्य में एक समान लक्ष्य के साथ काम करें। न्याय, शांति और प्रेम के माध्यम से उच्च चेतना की ऊर्जा के साथ कार्य करते हुए वही प्रदान करें जो वाहेगुरु जी हमसे चाहते हैं।

पंजाब को खोई हुई गरिमा वापस दिलाएंगे

डॉ नवजोत कौर ने पोस्ट में आगे लिखा कि हम पंजाब को उसकी खोई हुई गरिमा दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ताकि वह फिर से एक स्वर्णिम राज्य बन सके। जहां लोग प्रेम, साझेदारी, न्याय, स्वतंत्रता के अधिकार और नि:स्वार्थ सेवा के उद्देश्य के साथ आध्यात्मिक विकास की राह पर चलें और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने लक्ष्य, मूल्यों और दृष्टिकोण को प्राप्त करें। डॉ नवजोत कौर सिद्धू ने लिखा कि हम एक ऐसी सरकार देंगे जो जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा चलाई जाए। पंजाब के लोगों की सरकार होगी। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए, आध्यात्मिक गुरुओं की सहायता से ठीक किया जाएगा।

यूपी के शिक्षामित्रों को मई से मिलेगा बढ़ा मानदेय

- 1.43 लाख शिक्षामित्रों और 24 हजार अनुदेशकों को राहत

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकार पर अतिरिक्त बोझ

लखनऊ (एजेंसी)। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष पांच सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी, जिसे अब एक अप्रैल से लागू कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय एक मई से उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके तहत परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को अब 18 हजार रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इससे पहले शिक्षामित्रों को 10 हजार और अनुदेशकों को 9 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा था। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 1,42,929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं। इनमें से 1,29,332 शिक्षामित्रों का मानदेय अब तक समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में दिया जाता रहा है। मानदेय बढ़ने के बाद इन पर 1138.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा, जिसे प्रदेश सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से नव नियुक्त सूचना आयुक्तों ने की सौजन्य भेंट

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सोमवार को समत्व भवन में नव नियुक्त सूचना आयुक्त श्री राजेश भट्ट और श्री आलोक नागर ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सूचना आयुक्तों को बधाई एवं मंगलकामनाएं दीं।

आसिफ रजा ने आशीष पांडे बनकर किया रेप

गर्भवती पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई एफआईआर

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में एक छात्रा के साथ पहचान छिपाकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता प्राइवेट यूनिवर्सिटी की छात्रा बताई जा रही है। उसने आरोप लगाया कि आसिफ रज़ा नामक युवक ने खुद को आशीष पांडे बताकर उससे दोस्ती की और बाद में प्रेम संबंध बनाकर करीब डेढ़ साल तक शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता के अनुसार, इस दौरान युवक के दो अन्य दोस्त भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। जब वह गर्भवती हुई तो आरोपियों ने उस पर गर्भपात का दबाव बनाया। मना करने पर युवक ने अपनी असली पहचान उजागर की और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने लगा।

पीड़िता का कहना है कि उसे लगातार धमकाया गया। मामले की शिकायत पीड़िता ने लगभग एक माह पहले महिला थाने में दर्ज कराई थी। सोमवार को पीड़िता सामने आई। लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा है कि शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्य आरोपी आसिफ रज़ा बिहार का निवासी बताया जा रहा है। वह फिलहाल फरार है।

पूर्व सीएम उमा भारती ने ठेले पर बेचे पोहे-जलेबी

टीकमगढ़ में अपने बंगले के सामने दुकान लगाई; प्रशासन से बोलीं- गरीबों की रोजी-रोटी मत छीनो

टीकमगढ़ (नप्र)। टीकमगढ़ में मंगलवार (7 अप्रैल) सुबह पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सड़क किनारे हाथठेला लगाकर पोहा-जलेबी बेची। उन्होंने एक दिन पहले हटाए गए छोटे दुकानदारों को वापस ठेले लगाने के लिए बुलाया। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि गरीबों की रोजी-रोटी नहीं छीनी जाए। दरअसल, सोमवार को नगर पालिका, एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने सिविल लाइन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। इस दौरान जेसीबी से

कई छोटी दुकानें और हाथठेले हटा दिए गए थे। उमा भारती ने इस कार्रवाई का विरोध किया था और छोटे दुकानदारों को हटाने को गलत बताया था। इसी को लेकर मंगलवार सुबह वे सिविल लाइन रोड स्थित बंगले से निकलकर हाथठेले पर पहुंचीं। यहां खुद पोहा-जलेबी बेचकर दुकानदारों का समर्थन किया। उन्होंने हाथठेला वालों से दोबारा सड़क किनारे ठेले लगाने को कहा।

उमा बोलीं- प्रशासन पहले दुकानों के लिए जगह दे, बाद में हटाए- उमा भारती ने कहा कि पार्षदों ने पहले स्थान चिह्नित करने को कहा था। तीन-चार स्थान भी बताए थे। प्रशासन पहले दुकानों के लिए जगह दे, बाद में हटाए। उन्होंने हटाए गए दुकानदारों से अपील की कि वे वापस आएं और यहीं दुकानें लगाएं, मैं उनके साथ हूं। उनके ठेलों को यहां से नहीं हटने दिया जाएगा।

प्रशासन से बात करूंगी, सभी के ठेले वापस यहां लगाए जाएंगे- उमा भारती से पूछा गया कि क्या उन्होंने प्रशासन से बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसका पता चला है। मैं अभी प्रशासन से बात करूंगी। सभी के ठेले वापस यहां लगाए जाएंगे।

राज्यपाल आरोग्य भारती की नेचुरोपैथी कार्यशाला में हुए शामिल

स्वस्थ जीवन का आधार है इन्द्रियों पर नियंत्रण : राज्यपाल श्री पटेल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि नेचुरोपैथी स्वस्थ जीवन की मार्गदर्शिका है। उन्होंने कहा कि मन चंचल होता है, उसे नियंत्रित करना ही स्वस्थ जीवन का आधार है। स्वस्थ जीवन के लिए इन्द्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। प्रकृति ने शरीर को बनाने और बिगाड़ने की समान शक्ति मानव को दी है। राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के ज्ञान-विज्ञान सभागार में आरोग्य भारती की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि आयुर्वेद प्रकृति द्वारा प्रदान की गई औषधियों का विज्ञान है, जिसका प्रभाव भले ही धीरे-धीरे होता है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा वातावरण का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हमारे पूर्वज इसीलिए ऋतु अनुसार भोजन बदलते रहते थे। उन्होंने गुजरात के डांग क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि अंचल में बहुत हरियाली है, वहाँ पर ट्रायबल आबादी रहती है, लेकिन इस क्षेत्र के ट्रायबल्स में सामान्यतः मिलने वाला अनुवांशिक रोग सिकल सेल रोग बहुत कम मिलता है। यह बताता है कि प्रकृति का मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए पानी अधिक पीने, तैलीय पदार्थ कम खाने, कम

से कम 6 घंटे सोने और मिलेट के सेवन के लिए प्रेरित किया।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि नेचुरोपैथी केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन जीने के दृष्टिकोण और समग्र जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने कहा कि नेचुरोपैथी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खान-पान, प्रदूषण और तनाव से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सरल, सुरक्षित और प्रभावी समाधान देती है। उन्होंने बताया कि प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित नेचुरोपैथी का मानना है कि यदि व्यक्ति प्रकृति के अनुरूप जीवन बिताए, तो अनेक रोगों से बच सकता है। वास्तव में नेचुरोपैथी केवल उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन दर्शन है, जिसमें जल, वायु, सूर्य, मिट्टी और संतुलित आहार के माध्यम से शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाया जाता है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पोषण अभियान, आयुष्मान योजनाओं, योग एवं आयुष आधारित विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों से लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण को कम करने, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने तथा स्वच्छता जागरूकता की अनेक नई पहलें की हैं।

राज्यपाल ने सभी उपस्थित जनों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प–स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की सिद्धि में सक्रिय सहयोग करें। नेचुरोपैथी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर, दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने समाज में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की जनहितकारी पहल के लिए आरोग्य भारती को बधाई दी।

श्री अशोक कुमार वार्ष्णेय ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा के तार्किक, वैज्ञानिक आधार द्वारा जन जागृति के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान के इस युग में चमत्कार के रूप में उपचार की सोच सही नहीं है। यह समझना होगा कि रोग होने और उसका उपचार करने–दोनों में समय लगता है। उन्होंने सभी चिकित्सकीय पद्धतियों के प्रति समन्वयकारी दृष्टिकोण रखने और सफलता के अनावश्यक दावों से बचने का परामर्श दिया।

छेड़छाड़ से परेशान नौवीं की छात्रा ने आग लगा ली

बीना (सागर) (नप्र)। सागर जिले के खुरई में छेड़छाड़ से परेशान नौवीं की छात्रा ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसे सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

घटना 5 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे मालथौन थाना इलाके की है। थाना प्रभारी नवीन जैन ने बताया कि दो नामजद सहित चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। चारों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं।

तीन महीने से कर रहा था परेशान- 14 वर्षीय छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि छात्रा के पिता ने बताया कि बेटी मालथौन के सरकारी स्कूल में नौवीं क्लास में पढ़ती है। वह रोज बस से आना-जाना करती थी। 6 किमी दूर दूसरे गांव में रहने वाला एक लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ता था।

वह भी बस से आता-जाता था, लेकिन तीन महीने से वह बेटी को परेशान कर रहा था। आए दिन फोन कॉल करता था। एक बार उसे समझाया कि वह ऐसी हरकत न करे, लेकिन वह नहीं माना।

प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव 3 दिन आंधी-बारिश

भिंड, श्योपुर में ओले गिरने का अलर्ट, ग्वालियर-शिवपुरी समेत 11 जिलों में बारिश

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। अगले कुछ घंटे के दौरान ओले और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने शाम के समय भिंड और श्योपुर में मध्यम गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। वहीं, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, सतना के चित्रकूट और रीवा जिलों में हल्की गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। यहां बारिश भी होगी।

करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने धूल भरी आंधी का असर पैदा किया। वहीं, भोपाल में भी बादल छाए हैं।मौसम केंद्र भोपाल ने 9 अप्रैल तक तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को 34 जिलों में अलर्ट है। 8 और 9 अप्रैल को भी ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के जिलों में सिस्टम का असर रहेगा।

तेज आंधी भी चलेगी- मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में तेज आंधी भी चलेगी। कुछ जिलों में इसकी अधिकतम रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रहेगी। बाकी में 30 से 40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चलेगी।

- **11 अप्रैल को नया सिस्टम-** मौसम विभाग की माने तो 11 अप्रैल को उत्तर-पश्चिमी हिस्से में नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव होगा। जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है।
- **अप्रैल में एमपी में दिखा कश्मीर जैसा नजारा-** इससे पहले 4, 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश में सिस्टम की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिल चुकी है। 4 अप्रैल को तो 14 जिलों में ओलावृष्टि और 39 जिलों में तेज आंधी-बारिश का दौर रहा था।

रविवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा। कहीं तेज आंधी चली तो कहीं बारिश भी हुई। सोमवार को कहीं-कहीं बारिश का दौर बना रहा।

- **50 से 60 किमी/प्रतिघंटा से चलेगी आंधी-** मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में तेज आंधी भी चलेगी। कुछ जिलों में इसकी अधिकतम रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रहेगी।

छिपकली कांड के बाद बंद कैंटीन, टिफिन पर भी रोक

आरजीपीवी गेट पर छात्रों ने किया प्रदर्शन

भोपाल (नप्र)। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छिपकली कांड के बाद कैंटीन बंद होने के बाद छात्रों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बाहर से आने वाले टिफिन पर भी रोक लगा दी, जिससे छात्रों को रात में भोजन नहीं मिल पाया।

इसी के विरोध में सोमवार-मंगलवार रात 12 बजे तक मुख्य गेट पर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। भूखे छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और व्यवस्था सुधारने की मांग की।

छात्रों का कहना है कि इस घटना के बाद से उन्हें नियमित भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी दिनचर्या और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही हैं।

टिफिन रोकने पर भड़के छात्र- प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर टिफिन लेकर आने वाले व्यक्ति को गार्ड्स ने रोक दिया। छात्रों का कहना है कि जब कैंटीन बंद है, तो बाहर से खाना आने देना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने इस पर भी पाबंदी लगा दी है। इससे छात्र रात में भूखे रहने को मजबूर हो गए।

सीवी रमन बॉयज हॉस्टल के 40 से 50 छात्र करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य गेट तक पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पूर्व वार्डन व वरिष्ठ फैकल्टी के खिलाफ भी विरोध जताया।

छात्र बोले- बाहरी लोगों को नहीं रोकते

छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में बाहरी लोग आकर विवाद करते हैं, तब उन्हें नहीं रोका जाता, लेकिन छात्रों के खाने के टिफिन को रोक दिया जाता है। इस दोहरे रवैये को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखी गई। एक छात्र ने बताया कि मंगलवार से मिड टर्म परीक्षा शुरू हो रही है। छात्र दिनभर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन रात में खाने की व्यवस्था नहीं होने से परेशानी बढ़ गई। छात्रों का कहना है कि परीक्षा के समय इस तरह की अव्यवस्था उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।

एमपी में कांग्रेस करेगी 9 अप्रैल को 'क्रूर विश्वासघात' आंदोलन

सीएम यादव और मंत्री शिवराज पर किसानों को बिचौलियों के हवाले करने का आरोप लगाया

भोपाल/ इंदौर (नप्र)। मध्य प्रदेश कांग्रेस 9 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों की बदहाली और सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेंगी। प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों को बिचौलियों के हवाले करने का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है और प्रदेश का अन्नदाता आज अपने ही हक के लिए सड़कों पर आने को मजबूर है।

2700 का वादा और 40 का मजाक- वर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने 2700 प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार ने मात्र 40 रूपए का बोनस देकर किसानों के साथ ऊंट के मुंह में जीरा वाला व्यवहार किया है। यह किसानों के साथ सीधा-सीधा क्रूर विश्वासघात है।

पड़ोसी राज्य राजस्थान में 150 रूपए बोनस दिया जा रहा है, जबकि मध्यप्रदेश का

किसान अपने हक के लिए भटक रहा है। वहीं सरकार ने खरीदी की तारीखों को तीन बार आगे बढ़ाया है।

प्रदेश का अन्नदाता आज अपनी फसल का उचित मूल्य पाने के लिए दर-दर भटक रहा है। समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मंडियों में अव्यवस्था, खरीदी में देरी और बारदाने की कमी के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है।

ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी किसानों की इस पीड़ा को समझती है और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगी। 9 अप्रैल को होने वाला प्रदेशव्यापी आंदोलन, किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक निर्णायक संघर्ष होगा।

वर्मा ने आगे कहा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम में 10 अप्रैल और अन्य संभागों में 15 अप्रैल से खरीदी का निर्णय केवल इसलिए लिया गया है ताकि किसान घबराकर अपनी फसल कम दामों में व्यापारियों को बेच दे।

चलती कार से महिला को फेंका

हॉस्पिटल में 22 घंटे बेहोश रहने के बाद अब लापता; सीने में चुभे थे स्टेप्लर पिन

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के भोपाल में लहारपुर ब्रिज के पास अज्ञात कार सवारों ने 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को चलती कार से बाहर फेंक दिया। सीने में स्टेप्लर की पिन चुभी हुई थीं। खून से लथपथ थी। तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि 22 घंटे बेहोश रहने के बाद अब महिला हॉस्पिटल से लापता हो गई है। मामला बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब ढाई बजे एक तेज रफ्तार कार लहारपुर ब्रिज के पास नाले के किनारे पहुंची। कार की रफ्तार धीमी करते ही आरोपियों ने बुजुर्ग महिला को बाहर फेंक दिया। कार को तेजी से लेकर फरार हो गए।

चश्मदीद महिला ने देखी पूरी घटना

इस पूरी घटना को एक स्थानीय महिला ने देखा। उसने तुरंत आसपास के लोगों को जानकारी दी। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने एक स्वयंसेवी संस्था 'चित्रांश ह्यूमन वेलफेयर' को सूचना दी, ताकि घायल महिला की मदद की जा सके।

बेहोशी में सिर्फ 'सलकनपुर' बोल पा रही महिला- महिला बेहोशी की हालत में है और अपना नाम नहीं बता पा रही है। वह केवल सलकनपुर शब्द ही बोल पा रही है। उसके हाथ पर नाम गुदा हुआ मिला है। हालांकि, वह कहां की रहने वाली है और उसकी पहचान क्या है। यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

संस्था और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाई गई- सूचना मिलते ही संस्था के मोहन सोनी और पारस मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की मदद से घायल महिला को तत्काल हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।

संपादकीय

पुलिस निरंकुश नहीं हो सकती

कोरोना के दौरान तमिलनाडु में बाप बेटे की पुलिस हिरासत में मौत के बेहद गंभीर मामले में राज्य की एक अदालत द्वारा 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा देने का फैसला न केवल अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है बल्कि यह समूचे पुलिस तंत्र की निरंकुशता के लिए तगड़ा सबक भी है। दोनों बाप बेटे का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने कोरोना लॉक डाउन के दौरान अपनी दुकान खोलने का दुस्साहस किया था। तमिलनाडु की मदुरै सेशन कोर्ट ने सोमवार को सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (विरलतम) बताया। कहा कि अत्यधिक बर्बरता और सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। कोर्ट ने सभी दोषियों को मृतकों के परिजन को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा। गौरतलब है कि यह मामला 2020 का है। जिसकी सुनवाई छह साल तक चली। इस मामले में कुल 10 आरोपी थे। एक की कोविड के दौरान मौत हो गई। इस प्रकरण में 19 जून 2020 को पुलिस ने मोबाइल कारोबारी पी. जयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स को हिरासत में लिया था। आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली रखी थी। दोनों को सथानकुलम पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

वहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जहां कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों के साथ थाने में रातभर मारपीट की गई। उनके शरीर पर गंभीर चोट और खून बहने के निशान थे। आरोपियों को 23 मार्च 2026 को मदुरै की सेशंस कोर्ट में पेश किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए। सीबीआई ने इस प्रकरण में एक इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान एक महिला कांस्टेबल ने बयान दिया कि पिता-पुत्र को पूरी रात पीटा गया था। थाने में टेबल और लाठियों पर खून के निशान थे। यह गवाही मामले में अहम सबूत बनी। फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी. मुथुकुमारन ने सीबीआई की दलील को माना कि हिरासत में दोनों को योजनाबद्ध तरह से टॉर्चर किया गया। इसलिए अधिकतम सजा दी गई। हालांकि जांच में यह भी सामने आया कि सथानकुलम थाने का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित नहीं रखा गया। रिकॉर्डिंग रोजाना अपने आप डिलीट हो जाती थी, जिससे महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिल पाए। जाहिर है कि कानून की रक्षा करने वालों ने ही बाप बेटे की हत्या का पाप किया और फिर उसे छुपाने की हर संभव कोशिश की। पुलिस का काम पीड़ितों की रक्षा करना है न कि खुद पीड़ा देना। इस दृष्टि से निचली अदालत का यह फैसला स्वागतेय और मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला है। लोकतंत्र में पुलिस अपराधियों की तरह संवेदनहीन तरीके से काम नहीं सकती, क्योंकि वह एक संवैधानिक संस्था है। इस मामले में चाहती तो पुलिस सामान्य अपराध कायम कर बाप बेटों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी। इस फैसले से उन दोनों दिवंगत पिता पुत्रों के परिजनों को जरूर राहत मिली होगी। हालांकि कोर्ट द्वारा फांसी की सजा पर अमल की बहुत लंबी प्रक्रिया है। यह काम सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि के बाद ही संभव है। हालांकि पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी बहुत सख्त रहा है। इसलिए माना जा सकता है कि सर्वोच्च अदालत की निचली अदालत के फैसले को कायम रखेगी। जो फैसला हुआ है, वो आगे के लिए भी नजीर बनेगा। भारत जैसे लोकतंत्र में लोक सबसे ऊपर है। यहां पुलिस को तानाशाही की तरह बेलगाम होकर काम करने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती।

रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आह्वान

नजरिया

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता।

बोल्शेविकों ने 1917 में जब रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। क्रांतिकारियों को लेकर भारत सरकार में व्याप्त भ्रम को इसने और भी बढ़ावा दे दिया। इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने 'भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित आपराधिक षड्यंत्रों के स्वभाव और उसके फैलाव' का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। जिससे वे क्रांतिकारी आंदोलन से उपजे (काल्पनिक/वास्तविक) खतरों से निपटने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान प्रस्तुत कर सके। उक्त समिति में चार सदस्य थे दो ब्रिटिश और दो भारतीय और इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट कर रहे थे। 1918 में न्यायाधीश रॉलेट ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की जिसे दो भागों में विभाजित किया गया था। रिपोर्ट के पहले हिस्से में हिंसा से जुड़े कृत्यों का वर्णन किया गया था जिसमें हत्या, घात लगाकर हत्या, डकैती और बमबारी शामिल थे। इसमें बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों पर अलग से एक-एक अध्याय था और बंगाल पर सबसे अधिक पांच अध्याय लिखे गए थे। न्यायाधीश रॉलेट ने कहा कि 'हमारी समिति के द्वारा जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए थे उनसे यह साबित होता है कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य हिंसक साधनों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है और इस बीच सरकारी अधिकारियों की हत्या करना है और भारतीय सेना से जो भी सहायता हासिल हो सके हासिल करना था और अपने देशवासियों को लूटकर अपने मकसद के लिए धन का इंतजाम करना था'। रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा क्रांतिकारियों के आतंक का दमन करने और उन्हें पराजित करने से संबंधित था। न्यायाधीश रॉलेट ने कहा कि 'भारत में मुकदमों की लंबी अवधि' रहती हैं। इसके बरक्स राजद्रोह से संबंधित अपराधों की सुनवाई बिना जूरी के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। इस बाबत उनका तर्क था कि 'यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दंड या दोषमुक्ति का फैसला तेजी से हो ताकि दंड का एक नैतिक असर कायम हो सके और इसलिए भी कि लंबी सुनवाई उत्तेजना बढ़ती है उसे भी रोका जा सके'। समिति ने सलाह दी कि सारी सुनवाई कमरे में हो और प्रेस व आम जनता की निगाह से बाहर हो ताकि सुनवाई का कोई भी हिस्सा सार्वजनिक न हो सके। इस रिपोर्ट की एक प्रति जब एडविन मोंटेग्यू को लंदन में मिली तो वे निराश हो गए। उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा, 'इस रिपोर्ट में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे अरुचिकर लग रहा है'। जब युद्ध अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, तब भी रॉलेट ऐसे कठोर प्रावधानों को क्यों बनाए हुए हैं? वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने रिपोर्ट के पक्ष में मोंटेग्यू को एक जवाबी पत्र लिखा। जिसमें उन्होंने लिखा कि 'बंगाल के अराजकतावादी आंदोलन की सूरत में मेरी सरकार के लिए रॉलेट समिति के प्रतिवेदनों के अनुसार कानून बनाए बिना कार्य करना असंभव है'। उन्होंने उम्मीद की कि 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस प्रस्तावित कानून को अपनी सहमति प्रदान करेंगे जो भारत में हमारे मित्रों की कुछ अपराधियों से सुरक्षा के लिए जरूरी है'। गांधी जी रॉलेट समिति से वाकिफ नहीं थे क्योंकि इस रिपोर्ट की प्रति किसी भी भारतीय नेता को नहीं दी गई थी। इस दौरान गांधी कई स्वास्थ्यगत समस्याओं से ग्रसित भी थे और स्वास्थ लाभ ले रहे थे। 8 फरवरी 1919 को गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय जी को पत्र लिख कर उस 'घृणित' रॉलेट विधेयक के खिलाफ और उनके वापस न लिए जाने की स्थिति में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने श्रीनिवास शास्त्री और मदन मोहन मालवीय जी दोनों से कहा कि इस विधेयक के खिलाफ इंम्पीरियल लेजिस्लेटिव कॉउंसिल से आपको त्यागपत्र भी दे देना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि रॉलेट विधेयक 'दमन की सुनिश्चित नीति के सबूत' हैं और ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि सविनय नागरिक अवज्ञा वैयक्तिक और सार्वजनिक स्वतंत्रता के हरेक प्रेमी का कर्तव्य है। 9 फरवरी 1919 को उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय मित्र को पत्र लिखा। जिसमें उन्होंने लिखा कि 'रॉलेट विधेयक ने मुझे बेहद आंदोलित कर दिया है। ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी'। गांधी जी ने फरवरी के आखरी सप्ताह में साबरमती आश्रम में एक बैठक आयोजित की जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, बंबई के कारोबारी उमर सोबानी और राष्ट्रवादी अखबार क्रॉनिकल के इंग्लैंड में जन्मे भारत-प्रेमी संपादक बी.जी.हॉर्निमन थे।

इस बैठक में सत्याग्रह की प्रतिज्ञा का एक खाका खींचा गया। जिसमें रॉलेट विधेयक के वापस न लिए जाने की स्थिति में गिरफ्तारी देने वालों के हस्ताक्षर थे। 24 फरवरी को गांधी जी ने वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा 'तानाशाही सरकारें' भी आखिरकार अपनी सत्ता का स्रोत शासितों की इच्छा में ही पाते हैं। चेम्सफोर्ड ने गांधी जी के इस पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया। गांधी जी ने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए दिल्ली का दौरा किया। इस मुलाकात का वर्णन उन्होंने देवदास को लिखे अपने पत्र में किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि 'एक अंग्रेज को तर्क से नहीं झुकाया जा सकता, वह महज हालात से मजबूर होकर ही झुकता है'। फरवरी की शुरुआत में ही गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन के बारे में सोच लिया था और महीने भर के भीतर ही उन्होंने इसके लिए देशभर से समर्थन जुटा लिया था। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया था। गांधी जी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को एक अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया। गांधी जी ने बंबई में हड़ताल का नेतृत्व करने का निर्णय लिया था। वे सुबह साढ़े छह बजे चौपाटी के तट पर पहुंचे। 8 बजे तक वहां करीब 150000 लोगों की विशाल भीड़ इकट्ठी हो गई। जिसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान, पारसी और एक अंग्रेज भी शामिल था। उन्होंने तट पर उपस्थित लोगों से 'दिल्ली के निर्दोष लोगों' के बलिदान को याद दिलाते हुए उनसे मांग की कि वे यह शपथ लें कि जब तक शासक वर्ग का हृदय मुलायम न हो जाए वे लोग नागरिक सविनय अवज्ञा जारी रखकर खुद को तकलीफ देते रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना में भी एक बड़ी जनसभा हुई जिसमें 10000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और यहां लगभग सारी दुकानें भी बंद रहीं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और मिदनापुर में भी दुकानें बंद रहीं। मद्रास में पूर्ण बंद रहा और लगभग 100000 लोग समुद्र तट पर जमा हुए। मद्रास प्रेसीडेंसी के अन्य शहरों में भी गांधी जी की हड़ताल के आह्वान का बड़ा असर दिखाई पड़ा। बंबई से प्रकाशित एक उर्दू साप्ताहिक ने इस हड़ताल को शानदार कामयाबी करार दिया था। साप्ताहिक ने लिखा कि 'सरकार द्वारा उस कानून को पारित किए जाने से हिंदू और मुसलमान पानी और शक्कर की तरह घुलमिल गए हैं। यह एक वास्तविक जन-उभार था'। हड़ताल का असर अन्य शहरों और कस्बों पर भी पड़ा। हर स्थान पर धार्मिक एकता दिखाई दी। कराची के स्थानीय अखबार ने लिखा कि 'कराची ने अपनी दुकानों और व्यापार केंद्र बंद रखेः आखिर इतिहास में इस तरह की विलक्षण बातें कब हुई थीं ? ....कल के प्रतिरोध से हर कोई चित्त को आह्लादित कर देने वाली इस बात को लेकर प्रभावित था कि उस प्रदर्शन में किसी तरह की साम्प्रदायिक, संकीर्ण और भेदभावकारी बातें नहीं थीं। वे कल भी हिंदू, मुसलमान, पारसी, जैन या अन्य धर्मी थे लेकिन आज वे सभी एक ही भारतीय समुदाय से संबंध रखते हैं। उन सभी ने विविध धर्मों के बीच में एक ही धर्म-आत्मसम्मान का अनुभव किया यानी वो धर्म जो मानवता की सेवा के लिए भारत के अधिकार की सुरक्षा का धर्म था। 6 अप्रैल के बाद गांधी जी ने सत्याग्रहियों के लिए पर्चों की एक श्रृंखला छपवाई। एक पर्चे में ऐसी किताबों की सूची जारी की गई जो सेंसर द्वारा प्रतिबंधित थी। इस सूची में मिश्र के मुस्तफा कमाल पाशा की जीवनी और खुद गांधी जी की हिंद स्वराज शामिल थी। इस तरह के प्रतिबंधित सामग्री को प्रकाशित कर सत्याग्रही गिरफ्तारी दे सकते थे और नए कानून के अनुसार प्रतिबंधित सामग्री को रखना भी अपराध था और इसके लिए दो वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान था। दूसरे पर्चे में सत्याग्रहियों से कहा गया कि वे 'स्वदेशी' का व्रत लें और सिर्फ सूती कपड़ा ही पहने जिसका उत्पादन, कताई और बुनाई भारत में ही हुई हो। तीसरे पर्चे में सत्याग्रहियों से ये शपथ लेने के लिए कहा गया था। 'ईश्वर को साक्षी मानकर हम हिंदू और मुसलमान ये घोषणा करते हैं कि हम एक-दूसरे के साथ भाई-भाई जैसे व्यवहार करेंगे, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा और एक की तकलीफ दूसरे की तकलीफ होगी और हर कोई एक-दूसरे की तकलीफ दूर करने की कोशिश करेगा। हम एक-दूसरे के धर्म और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के धार्मिक क्रियाकलापों में बाधा नहीं बनेंगे। धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा से हम हमेशा दूर रहेंगे'। काश गांधी आज जिंदा होते और धार्मिक असहिष्णुता और संकीर्णता के इस दौर से हम सभी को बचा लेते और हम सभी में विविधता के बावजूद एक सर्वव्यापी धर्म मानवता का धर्म निहित रहता और बचा रहता। हम सभी उसी मानवता के धर्म से बंधे रहते और एक-दूसरे के बरक्स खड़े नहीं होते।

कोयले से ऊर्जा उत्पादन की ओर लौटती दुनिया

सामयिक

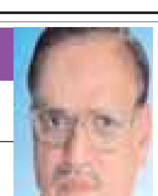

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

जलवायु परिवर्तन के घातक संकेतों के चलते दुनिया गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन की ओर तेजी से बढ़ी थी। किंतु पहले रूस-यूक्रेन, इजरायल-फिलीस्तीन और अब अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध ने ऐसे विकट हालात पैदा कर दिए हैं कि दुनिया ऊर्जा संकट की कमी झेलने लगी है। अतएव जिन देशों ने ऊर्जा उत्पादन के गैस आधारित उपाय कर लिए थे, वे अब अपने कोयले से चलने वाले बंद पड़े ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने की तैयारी में जुट गए हैं। क्योंकि इस युद्ध में तेल भंडारों के साथ गैस से बनने वाली बिजली संयंत्रों पर युद्ध के दौरान बड़े हमले हुए है। ईरान ने पश्चिम एशियाई देशों में स्थित अनेक ऊर्जा संयंत्रों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ अमेरिका एवं इजरायल ने ईरान के परमाणु और गैस ऊर्जा संयंत्रों को ध्वस्त कर दिया है। इस गल्फ वार ने दुनिया में गैस की किल्लत पैदा कर दी है। नतीजतन जापान, जर्मनी, बांग्लादेश, नीदरलैंड, पोलैंड और चेक गणराज्य जैसे देशों ने जीवाश्म ईंधन, अर्थात् कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को फिर से चालू करने का निर्णय ले लिया है। जबकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से यूरोप में कोयले से बिजली बनाने की क्षमता में 45 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी। दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लंबे समय से गैस आधारित बिजली को एक 'ब्रिज फ्यूल' के तौर पर बेचा जाता था। अर्थात् कोयले का एक ऐसा स्वच्छ विकल्प मिल गया था, जो सस्ता होने के साथ भरोसे का भी है। इसके प्रयोग में कार्बन का उत्सर्जन भी शून्य रहता है। अतएव ऊर्जा उत्पादन में इसकी उपयोगता निरंतर बढ़ रही थी। लेकिन ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों के चलते गैस का संकट लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी का दावा है कि गैस की कमी और उसकी बढ़ती कीमतों के चलते सरकारें, उद्योग और घर-परिवार दूसरे विकल्पों की तालाश करेंगे। इसलिए कोयले का इस्तेमाल होना तय है। कोयले से बिजली बनेगी तो कॉर्बन का भी बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होगा। इस विषयक गोल्डमेन सैक्स ग्रुप में कमोडिटीज रिसर्च का कहना है कि हम ऊर्जा आपूर्ति में आया दूसरा बहुत बड़ा झटका अनुभव कर रहे है। ऐसे में इस बात की आशंका है कि कई देशों को लंबे समय तक कोयले पर निर्भर रहना पड़ सकता है। गैस की कमी के चलते यूरोप और एशिया के कई देश कोयले से बिजली उत्पादन को मजबूर हो जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े गैस आयातक देशों में से एक जापान ने तो हि भी दिया है कि हम कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने जा रहे हैं। यूरोपीय देश भी 20 प्रतिशत से अधिक बिजली का उत्पादन कोयले से करने लग जाएंगे। इससे वायुमंडल में बढ़ते तापमान के वैश्विक उपायों को बड़ा झटका लग सकता है।

2018 का ऐसा वर्ष था, जब भारत और चीन में कोयले से बिजली उत्पादन में कमी दर्ज की गई थीं। नतीजतन भारत पहली बार इस वर्ष के 'जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक' में शीर्ष दस देशों में शामिल हो गया था। वहीं अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हुआ था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 'कॉप 25' जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 57 उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले देशों में से 31 में उत्सर्जन का स्तर कम होने के रुझान इस रिपोर्ट में दर्ज थे। उन्हीं देशों से 90 प्रतिशत कार्बन का उत्सर्जन होता रहा है। इस सूचकांक ने तय किया था कि कोयले की खपत में कमी सहित कार्बन उत्सर्जन में वैश्विक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। इस सूचकांक में चीन में भी मामूली सुधार हुआ था। नतीजतन वह तीसवें स्थान पर रहा है। जी-20 देशों में ब्रिटेन सातवें और भारत को नवीं उच्च श्रेणी हासिल हुई थी। जबकि आस्ट्रेलिया 61 और सऊदी अरब 56वें क्रम पर हैं। अमेरिका खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में इसलिए आ गया था, क्योंकि उसने जलवायु परिवर्तन की खिल्ली उड़ाते हुए इस समझौते से बाहर आने का निर्णय ले लिया था।

दुनिया की लगभग 37 प्रतिशत बिजली का निर्माण थर्मल पावरों में किया जाता है। इन संयंत्रों की भट्टी में कोयले को झोंका जाता है, तब कहीं जाकर बिजली का उत्पादन होता है। ब्रिटेन में हुई पहली औद्योगिक क्रांति में कोयले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1500 ईसवीं में बड़ी मात्रा में कोयले के उत्खनन की शुरूआत हुई थी। इसके बाद जिन देशों में भी कारखाने लगे, उनमें लकड़ी और कोयले का प्रयोग लंबे समय तक होता रहा। दुनिया की रेलें भी कोयले से ही लंबे समय तक चलती रही हैं। भोजन पकाने और ठंड से बचने के उपाय भी लकड़ी जलाकर किए जाते रहे हैं। अतएव धुएं के बड़ी मात्रा में उत्सर्जन और धरती के तापमान में वृद्धि की शुरुआत औद्योगिक क्रांति की बुनियाद रखने के साथ ही आरंभ हो गई थी। इसके बाद जब इन दुष्प्रभावों का अनुभव पर्यावरणविदों ने किया तो 14 जून 1992 में रियो डी जनेरियो में पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप जापान के क्योटो शहर में 16 फरवरी 2005 को पृथ्वी के बढ़ते तापमान के जरिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई। इस संधि में शामिल देशों ने ग्रीन हाउस अर्थात् मानव उत्सर्जित गैसों को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। दुनिया के वैज्ञानियों ने एक राय होकर कहा कि मानव निर्मित गैस सीओ-2 के उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो जीवाश्म ईंधन का पर्याय है। 192 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं।

लेकिन वर्तमान में चल रहे भीषण युद्धों ने हालात बदल दिए हैं। नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुए वैश्विक सम्मेलन में तय हुआ था कि 2030 तक विकसित देश और 2040 तक विकासशील देश ऊर्जा उत्पादन में कोयले का प्रयोग बंद कर देंगे। यानी 2040 के बाद थर्मल पावर अर्थात् ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले से बिजली का उत्पादन पूरी तरह बंद हो जाएगा। तब भारत-चीन ने पूरी तरह कोयले पर बिजली उत्पादन पर असहमति जताई थी, लेकिन 40 देशों ने कोयले से पल्ला झाड़ लेने का भरोसा दिया था। 20 देशों ने विश्वास जताया था कि 2022 के अंत तक कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों को बंद कर दिया जाएगा। आस्ट्रेलिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक व निर्यातक रियो टिंटो ने अपनी 80 प्रतिशत कोयले की खदानें बेच दीं थीं, क्योंकि भविष्य में कोयले से बिजली उत्पादन बंद होने के अनुमान लगा लिए गए थे। भारतीय व्यापारी गौतम अडानी ने इस अवसर का लाभ उठाया और अडानी ने 'आस्ट्रेलिया कोल कंपनी' बनाकर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड क्षेत्र में कोयला खदानें भी हासिल कर लीं। अडानी ने कारमिकेल कोयला खदान पर पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने के बाद 2019 से कोयले का खनन शुरू कर इसे बेचना भी आरंभ कर दिया है। अडानी ने ऑस्ट्रेलियाई मूल के 1500 बेरोजगारों को प्रत्यक्ष और 6,750 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देने का अनुबंध करके इस खदान से उत्खनन शुरू किया है। कोरोना के बाद 2022 में भारत में कोयले का संकट खड़ा हुआ था, तब आस्ट्रेलिया से ही भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने कोयला खरीदा था। 2019 तक यूरोप केवल 20 प्रतिशत बिजली का उत्पादन कोयले से करता था। ऊर्जा की शेष जरूरतों की आपूर्ति गैस से होती थी। इसलिए अनेक यूरोपीय देशों ने 2025 तक अधिकतर ताप विद्युत घरों को बंद करने की परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस से गैस की आपूर्ति बंद हो जाने के कारण इटली, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया ने अपने संयंत्रों में कोयले से बिजली उत्पादन आरंभ कर दिया था। इन फैसलों के चलते अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को कहना पड़ा था कि 2022-23 में यूरोपीय देशों में कोयले से बिजली का उत्पादन 7 से 10 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। जबकि पूरी दुनिया में कोयले की खपत आठ अरब टन हो जाएगी। कोयले की इतनी ही खपत 2013 तक होती थी। साफ है, कोयले की खपत बिजली उत्पादन के लिए बढ़ेगी तो कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा। अतएव धरती के तापमान में वृद्धि भी बढ़ेगी।

कटाक्ष

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

लेखक व्यंग्यकार हैं।

पुनर्जन्म का आधार कार्ड

बेलतारा गांव के राजनीति विशारद 'लल्लन बाबू' ने जब इस बार प्रधानी का बिगुल फूँका, तो उन्होंने 'स्मार्ट सिटी' और 'मुफ्त बिजली' के घिसे-पिटे वादों को ठेंगा दिखा दिया। उनका नया चुनावी शगूफा था–'पितृ-पेंशन और पुरखा-कनेक्ट योजना'। लल्लन बाबू का तर्क था कि नेता जीवितों की सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो पूर्वज स्वर्ग में बैठकर अपनी संतानों की दुर्दशा देख रहे हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं करता। उन्होंने घोषणा की कि यदि वे चुनाव जीते, तो गांव के श्मशान में 'वाई-फाई युक्त प्रेत-कॉलिंग सेंटर' बनवाएंगे, जहाँ से ग्रामीण सीधे अपने परलोकवासी दादा-परदादाओं से सलाह ले सकेंगे कि इस बार कौन सी भैंस खरीदनी है या किस लड़के की शादी कहाँ करनी है। गांव के भोले-भाले लोग, जो पितृ पक्ष में कौवों को रोटी खिलाकर थक चुके थे, अचानक 'टेक्नो-अध्यात्म' के इस जादुई जाल में ऐसे फंसे कि उन्हें अपनी वर्तमान गरीबी से ज्यादा पूर्वजों की 'नेटवर्क कनेक्टिविटी' की चिंता होने लगी।

प्रचार के अंतिम पड़ाव पर लल्लन बाबू ने गांव के पुराने कुएं के पास एक 'आत्मा-स्कैनर' मशीन स्थापित की, जो असल में एक कबाड़ हो चुका एक्सरे मशीन का ढांचा था जिस पर ढेर सारी चमकीली झिलमिलियां चिपकी थीं। उन्होंने दावा किया कि जो भी व्यक्ति उन्हें वोट देने की कसम खाकर इस मशीन के नीचे खड़ा होगा, उसे अपने अगले सात जन्मों का 'आधार कार्ड' और 'प्रोफेशनल बायोडाटा' तुरंत मिल जाएगा। विपक्षी उम्मीदवार 'घसीटा राम' बदहवास थे; वे स्कूल की मरम्मत और खाद की बात कर रहे थे, जबकि जनता को यह जानने की उत्सुकता थी कि अगले जन्म में वे राजा बनेंगे या पड़ोसी के घर के पालतू कुत्ते। लल्लन बाबू ने एक लाउडस्पीकर पर डरावनी और रहस्यमयी आवाज़ें रिकॉर्ड करके चला दीं, जिसे सुनकर ग्रामीणों को साक्षात 'गरुड़ पुराण' का लाइव टेलीकास्ट महसूस होने लगा। लोग अपनी मेहनत की कमाई चंदे के रूप में लल्लन बाबू के चरणों में अर्पित करने लगे ताकि उनका 'अगला जन्म' कम से कम सुरक्षित हो सके।

मतदान के अगले दिन जब लल्लन बाबू की प्रचंड जीत हुई, तो पूरा गांव अपना 'पुनर्जन्म का आधार कार्ड' लेने उनके दरवाजे पर कतारबद्ध हो गया। लल्लन बाबू ने एक बड़ा सा बक्सा खोला और उसमें से छोटे-छोटे खाली शीशे के टुकड़े (आईने) सबको बांटना शुरू कर दिया। जनता हक्की-बक्की रह गई, 'हुजूर, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, बस हमारा अपना चेहरा दिख रहा है!' लल्लन बाबू ने एक लंबी डकार ली और गंभीर स्वर में बोले– 'मूर्खों! पुनर्जन्म का आधार कार्ड यही आईना है। इसमें गौर से अपना चेहरा देखो; जिस इंसान ने एक कोरे वादे और कबाड़ की मशीन के चक्कर में अपना भविष्य और वर्तमान मुझे बेच दिया, वह अगले जन्म में 'गदहा' बनने की पूरी योग्यता अभी से हासिल कर चुका है! पूर्वज तो स्वर्ग में आराम कर रहे हैं, पर तुम लोगों ने मेरा अगला जन्म जरूर सुधार दिया।' जनता स्तब्ध खड़ी अपनी ही परछाई को देख रही थी और लल्लन बाबू अपनी नई पजेरो में बैठकर 'परलोक कल्याण विभाग' का बजट डकारने शहर की ओर कूच कर गए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

रंग बदलने के खतरे को लेकर गिरगिटों की हाई लेवल मीटिंग

व्यंग्य

डॉ. प्रेमचंद द्वितीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

पंडित शिवनारायण मॉर्निंग वॉक के दौरान बेफिजुल रंग जमाते बोले गर रंग न होते तो किसी की रंगत ही नहीं होती। किस्म किस्म के लोग रंग जमाने के लिए तरह-तरह के रंग बदलते हैं। दुनिया द्वारा रंग बदलने की खबर कॉलोनी के बगीचों में कुछ गिरगिटों को पता चली तो गिरगिट बोले हम यूं ही बदनाम है रंग बदलने में! ट्रंप नाम का मानव जीव रंग बदलने में हमसे ज्यादा उस्ताद है। ट्रंप हम गिरगिटों का पर्याय बन गए है।

रंग बदलने में बदनाम जब कुछ गिरगिट इकट्ठा हुए तो रंग बदल बदल कर थक चुका वृद्ध गिरगिट बोला हमारे देखा-देखी इंसान रंग बदलने में महारत हासिल कर चुके हैं ।

ट्रंप रंग बदलने में हमारे ब्रांड एम्बेसेंडर है। हममें और ट्रंप मैं मौलिक अंतर है हम गिरगिट त्वचा का रंग बदलते हैं केवल सुरक्षा के लिए लेकिन ट्रंप सियासी धाक जमाने के लिए कब वाचा बदल दे कोई ठिकाना नहीं है, राजनीतिक जाजम बिछाने के लिए रंग बदलने में कोई देर नहीं करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के पर्याय है । बार-बार रंग बदलने के लिए ट्रंप झूठ का का कारोबार चलाते हैं झूठ पर झूठ बोलकर सच को झुठलाने में माहिर हो चुके है। रंग बदलने और झूठ बोलने की कवायद से हमारे रंग बदलने के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। हम तो दो-चार तरह के प्राकृतिक रंगों को बदलकर अपने आप को बचाते हैं लेकिन मुंए इस तरह के इंसान तरह-तरह के रंग बदल बदल कर कईयों को बदरंग कर अपना रंग जमाने से नहीं चूकते हैं ।

वृद्ध गिरगिट के इस हताशा भरे बयान को सुनकर नए नवेले व किशोर गिरगिट जो रंग बदलने के प्रशिक्षण से गुजर रहा था। बोला ये इंसान जब भी रंग बदलने की बात आती है तो हमें दांव पर लगा कर कहते हैं गिरगिट की तरह रंग मत बदलो! लेकिन खुद एक, दो नहीं बीसियों बार रंग बदलते हैं और रंगीन नजारे को हथियाने का प्रयास करते हैं,अपनी झांकी जमाने के लिए रंग जमाते हैं।सियासी रंग जमाने के लिए कभी दो रंगी, कभी तिरंगी तो कभी बहूरंगी मुखौटा पहनकर सियासी रंग को हासिल करना चाहते हैं। ताकि जब भी रंग खेलने की या ढूंलने की बात आए तो रंग ढुले सरकार का और मिर्जा होली खेले , को अपना कर सरकारी रंग ढोल कर वे हमेशा रंगीन बने रहे।

यह सुनकर एक चपल गिरगिट बोला कि मैं एक दिन बगीचे में एक साहब के गमले के बगीचे के थ्रू उनके बंगले में पहुंच गया तो वहां जो मैंने देखा उसको देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। पहले तो साब मुझे देखकर बड़बड़ाए कि साला यह रंग बदलने वाला गिरगिट यहां आकर मेरे रंग बदलने की प्रवृत्ति की किरकिरी कर देगा ।कोई बाहर वाला इस गिरगिट को देखकर समझेगा कि यह वही साब है जो इस गिरगिट की तरह रंग बदलने में उस्ताद है। मेरे इस रंग बदलने के खौफ से उन्होंने पहले तो मुझ जैसे तुच्छ गिरगिट को नजरों से गिराने की कोशिश की क्योंकि वे लोगों को नजरों से गिरा गिरा कर वे गिराने के अभ्यस्त हो चुके थे।

इसी बीच इंसान के डर से अपने को बचाने के लिए एक गिरगिट साहब के पड़ोस में पहुंच गया तो अंदेशा हुआ कि अभी तक मैंने जितने रंग बदले इन गिरगिटो के कारण... मैं गिरगिटों की तरह रंग बदलने वाला साहब न.बन जाऊं,इस कारण उन्होंने अपने सारे नौकर चाकर को मुझे भगाने में लगा दिया। ताकि कॉलोनी वाले गिरगिट और उनके रंग बदलने के वाकिए से वाकिफ न हो सके।

गिरगिटों की चर्चा सुनकर सुनील भैया बोले अरे जब रंग जमाने की बात चली रही है तो एक दिन मेरे गांव में पंचतंत्र की कहानी सुनकर और उनसे प्रेरणा लेकर इलाके के माननीय, रंगे सियार, की झूठ की प्रवृत्ति को अपनाकर अपना रंग जमाने में सफल हो गए। वे बोले गिरगिट और,रंगे सियार, की कहानी के रंगों से जुड़ाव को देखकर रंगों से अपने बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव को सरोबार कर लिया ।वे बोले रंग और लोगों के चेहरे का अनूठा रिश्ता है। लोगों के चेहरे के रंग बदलते रहते है। वे बोले लाल पीले कैसरिया रंग चेहरों के बदलते रंगों के पासंग में भी नहीं लगते हैं! जब चेहरे का रंग उड़ता है तो डर, घबराहट हैरानी को जाहिर करता है। चेहरा वही है लेकिन रंग बदलने वाला चेहरा कभी खुशी,कभी गम, कभी सफलता,कभी कारगुजारियों को उजागर कर देता है ।जब चेहरे पर एक रंग आता है दूसरा जाता है तो घबराहट चरम पर होती है। चेहरे बेरंग हो जाते हैं और चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिखती है जब चेहरे पर लाल और गुलाबी रंग दिखता है तो ये रंग गुस्से और तमतमाए स्वरूप को बता देते हैं।

दृष्टिकोण

डॉ. मनीष जैसल

लेखक फिल्म समीक्षक हैं।

ईरान की जंग के बीच उनके सिनेमा पर एक नजर

ईरानी सिनेमा का इतिहास देखें तो यह हमेशा सत्ता और समाज के बीच एक जटिल संवाद की तरह विकसित हुआ है। शुरुआती दौर में, जब सिनेमा ईरान में आया, वह राजशाही और अभिजात वर्ग के मनोरंजन का साधन के रूप में एक आयातित माध्यम था। लेकिन धीरे-धीरे यह माध्यम आम लोगों तक पहुँचा और उसमें समाज की आकृतियाँ उभरने लगीं। बीसवीं सदी के मध्य तक आते-आते यह स्पष्ट होने लगा कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विचार और नियंत्रण का भी उपकरण हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे औपनिवेशिक संदर्भों में सिनेमा का उपयोग साम्राज्यवादी दृष्टि को स्थापित करने के लिए किया गया, ईरान में भी सिनेमा पर सत्ता की छाया लंबे समय तक बनी रही।

ईरान के मशहूर फ़िल्मकार जफ़र पनाही के ईरान लौटने की खबर है। युद्ध के इन हालातों के बीच प्रतीकात्मक रूप से उनका ईरान वापस लौटना किसी एक फिल्मकार की निजी यात्रा भर नहीं है; यह उस सिनेमा की वापसी है जो अपने ही देश में लगातार संदेह, निगरानी और दमन के बीच सांस लेता रहा है। पनाही का लौटना दरअसल एक जोखिम उठाना है, यह जानते हुए कि उनके लिए वहां प्रतिबंध, पूछताछ और कारावास की संभावनाएँ बनी हुई हैं। लेकिन इसी जोखिम में ईरानी सिनेमा की असली आत्मा दिखाई देती है। यह वह सिनेमा है जो सुविधा के बजाय सत्य को चुनता है, और निर्वासन की सुरक्षित दूरी के बजाय अपने समाज की असुविधाजनक निकटता में खड़ा रहना चाहता है।

ईरानी सिनेमा का इतिहास देखें तो यह हमेशा सत्ता और समाज के बीच एक जटिल संवाद की तरह विकसित हुआ है। शुरुआती दौर में, जब सिनेमा ईरान में आया, वह राजशाही और अभिजात वर्ग के मनोरंजन का साधन के रूप में एक आयातित माध्यम था। लेकिन धीरे-धीरे यह माध्यम आम लोगों तक पहुँचा और उसमें समाज की आकृतियाँ उभरने लगीं। बीसवीं सदी के मध्य तक आते-आते यह स्पष्ट होने लगा कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विचार और नियंत्रण का भी उपकरण हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे औपनिवेशिक संदर्भों में सिनेमा का उपयोग साम्राज्यवादी दृष्टि को स्थापित करने के लिए किया गया, ईरान में भी सिनेमा पर सत्ता की छाया लंबे समय तक बनी रही।

1960 के दशक में जो बदलाव आया, उसने इस छाया को चुनौती दी। 'ईरानी न्यू वेव' के रूप में जिस प्रवृत्ति का जन्म हुआ, उसने सिनेमा को एक नए बौद्धिक और कलात्मक आयाम में पहुँचा दिया। दारियूश मेहरजुई की 'द काउ' जैसी फिल्में केवल कथानक नहीं थीं, बल्कि मनुष्य की आंतरिक विघटन और सामाजिक यथार्थ का सूक्ष्म अध्ययन थीं। यह वह समय था जब सिनेमा ने अपने दर्शकों को चकाचौंध से हटाकर जीवन की वास्तविकताओं के सामने खड़ा करना शुरू किया। छोटे कस्बे, ग्रामीण परिवेश, सामान्य लोग, सब सिनेमा के केंद्र में आए और एक नई भाषा का निर्माण हुआ, जो सीधी कम और संकेतों से भरी अधिक थी।

1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरानी सिनेमा का यह संवाद और जटिल हो गया। नई सत्ता ने सिनेमा पर कड़े नियम लागू किए–विशेषकर नैतिकता, स्त्री-पुरुष संबंधों और सामाजिक व्यवहार को लेकर एक पहरा लगा। पहली नजर में यह लगा कि सिनेमा की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी और रचनात्मकता पर अंकुश लग जाएगा। लेकिन यही वह क्षण था जब ईरानी सिनेमा ने अपनी सबसे बड़ी खोज की। संकेतों और रूपकों की भाषा में वो कहा जिसे दुनिया ने देख अचंभा भी किया। सीधे कहने की जगह अब इशारों में बात होने लगी।

फ़िल्मकार अब्बास कियारोस्तामी ने इस भाषा को दार्शनिक गहराई दी। उनकी फिल्मों में घटनाएँ बहुत कम होती हैं, लेकिन प्रश्न अत्यंत बड़े होते हैं। 'टेस्ट ऑफ चेरी' में जीवन और मृत्यु का प्रश्न जिस सादगी से उठता है, वह किसी भी जटिल दार्शनिक विमर्श से कम प्रभावी नहीं। आप सोचिए अपनी ही मृत्यु के पहले ही फ़िल्म का एक किरदार अपने लिए कब्र खोदने का इंतज़ाम खोजने निकला है। वहीं 'व्हेयर इज द फ्रेंड्स होम' जैसी फिल्में यह दिखाती हैं कि नैतिकता किसी बड़े आदर्श में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे निर्णयों में छिपी होती है। यह सिनेमा दर्शक को उत्तर नहीं देता, बल्कि उसे सोचने के लिए अकेला छोड़ देता है।

ईरान के एक और फ़िल्मकार माजिद माजिदी ने इस परंपरा को मानवीय संवेदनाओं के स्तर पर और विस्तार दिया। 'चिल्ड्रेन ऑफ हेवन' जैसी फिल्में यह साबित करती हैं कि गरीबी की कहानी करुणा का प्रदर्शन नहीं, बल्कि गरिमा का चित्रण भी हो सकती है। दो बच्चों और एक जोड़ी जूतों के बीच बुनी गई कथा में पूरा सामाजिक ढांचा झलकता है। यहाँ बच्चों की दुनिया के माध्यम से समाज की जटिल संरचनाओं को बेहद सहजता से प्रस्तुत किया गया है। यही वह शैली है जिसमें ईरानी सिनेमा बिना किसी नाटकीयता के जीवन की सच्चाइयों को दर्शक के अनुभव का हिस्सा बना देता है।

जाफर पनाही इस परंपरा के भीतर एक अलग स्वर लेकर आते हैं–एक ऐसा स्वर जो अधिक प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी सीमाओं के भीतर रहकर काम करता है। 'द सर्कल' और 'ऑफसाइड' जैसी फिल्मों में समाज की संरचनात्मक असमानताओं को बिना किसी अलंकरण के सामने रखा गया है। पनाही का सिनेमा यह दिखाता है कि प्रतिबंध केवल विषय को नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति के तरीके को भी बदलते हैं। उनके यहाँ कैमरा एक गवाह की तरह है–जो देखता है, दर्ज करता है, लेकिन चिल्लाता नहीं।

ईरानी सिनेमा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है–हाशिए पर मौजूद जीवन की कहानियों को केंद्र में लाना। माजिद मजीदी की फ़िल्म बरान इसी दृष्टि का विस्तार है, जहाँ अफ़ग़ान शरणार्थियों के कठिन जीवन के बीच प्रेम और करुणा की एक मौन कथा विकसित होती है। लतीफ़ का चरित्र धीरे-धीरे संवेदनशीलता और त्याग की ओर अग्रसर होता है, जो यह दर्शाता है कि कठोर सामाजिक परिस्थितियाँ भी मानवीयता को समाप्त नहीं कर पातीं, बल्कि कई बार उसे और गहरा कर देती हैं।

इसी संवेदनात्मक परंपरा में द डे आय बिकम ए वीमेन स्त्री जीवन के विविध चरणों को प्रतीकात्मक और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। तीन अलग-अलग आयु वर्ग की महिलाओं के माध्यम से यह फिल्म सामाजिक बंधनों, स्वतंत्रता की आकांक्षा और पहचान के संघर्ष को सामने लाती है। ईरानी समाज की जटिलताओं के भीतर स्त्री के अनुभव को जिस सूक्ष्मता और संवेदनशीलता से फिल्म में व्यक्त किया गया है, वह इसे विशिष्ट बनाता है।

इसी कड़ी में ग़ुलाम रेज़ा रमेजानी की फिल्म हयात ईरानी सिनेमा के यथार्थवादी और मानवीय दृष्टिकोण को और गहराई देती है। एक छोटी बच्ची की शिक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष की कहानी यह दर्शाती है कि साधारण जीवन में भी असाधारण संवेदनाएँ और संघर्ष छिपे होते हैं।

इन फ़िल्मों से ईरानी सिनेमा की भव्यता नहीं, बल्कि जीवन की सादगी, मानवीय गरिमा और गहरी संवेदनात्मक दृष्टि से अपनी पहचान दिखाई पड़ती है।

वर्तमान समय में ईरान का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य जिस तरह का है, उसने सिनेमा को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। हाल के वर्षों में हुए जनांदोलनों, विशेषकर महिलाओं के नेतृत्व में उभरे प्रतिरोध, ने यह स्पष्ट किया है कि समाज के भीतर गहरी बेचैनी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण, इंटरनेट पर निगरानी और सांस्कृतिक गतिविधियों पर दबाव–ये सब उस वातावरण का हिस्सा हैं जिसमें आज का ईरानी सिनेमा काम कर रहा है।

इसी संदर्भ में पनाही की वापसी को समझना जरूरी है। यह वापसी किसी नॉस्टेल्जिया का परिणाम नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता का संकेत है। यह उस विश्वास की पुनः पुष्टि है कि सिनेमा अपने समाज से कटकर जीवित नहीं रह सकता। भले ही उसके लिए जोखिम क्यों न उठाना पड़े। आज कई ईरानी फिल्मकार देश के भीतर और बाहर, दोनों जगहों पर काम कर रहे हैं। एक ओर निर्वासन का सिनेमा है, जो अपेक्षाकृत स्वतंत्र है; दूसरी ओर वह सिनेमा है जो भीतर रहकर सीमाओं के साथ संघर्ष करता है। लेकिन दोनों के बीच एक साझा धारा है–सत्य को दर्ज करने की।

अंडरग्राउंड सिनेमा का उभार इसी धारा का विस्तार है। यह सिनेमा किसी संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता इसी में है कि यह सीधे जीवन से निकलता है।

महिला फिल्मकारों की बढ़ती उपस्थिति इस परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण आयाम है। फ़रूग़ फ़र्रुख़ज़ाद की परंपरा आज नई पीढ़ी में नए रूपों में दिखाई देती है। यह सिनेमा अब केवल महिलाओं के बारे में नहीं, बल्कि उनके दृष्टिकोण से बन रहा है। इसमें निजी और सार्वजनिक के बीच की सीमाएँ धुंधली हो रही हैं, और पहचान के प्रश्न अधिक तीखे होकर सामने आ रहे हैं।

ईरानी सिनेमा की एक दिलचस्प विशेषता यह भी है कि वह जितना अपने देश में संघर्ष करता है, उतना ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है। विश्व के प्रमुख फिल्म समारोहों में इसकी उपस्थिति यह दिखाती है कि इसकी भाषा सार्वभौमिक है। यह स्थानीय होते हुए भी वैश्विक है। इसके प्रश्न किसी एक समाज तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक मानवीय अनुभव से जुड़े हैं।

भविष्य की ओर देखें तो ईरानी सिनेमा अनिश्चितताओं के बीच खड़ा दिखाई देता है। सेंसरशिप और राजनीतिक दबाव बने रहेंगे, यह लगभग तय है। लेकिन इसके साथ ही नई तकनीक, वैश्विक मंच और नई पीढ़ी की दृष्टि ऐसे तत्व हैं जो इसे लगातार नया रूप देते रहेंगे। संभव है कि आने वाले समय में ईरानी सिनेमा और अधिक विभाजित रूप में दिखाई दे–एक ओर संस्थागत सीमाओं के भीतर काम करने वाला सिनेमा, दूसरी ओर पूरी तरह स्वतंत्र और वैश्विक सिनेमा। लेकिन इन दोनों के बीच जो साझा तत्व रहेगा, वह है–मानव जीवन की जटिलताओं को समझने और उन्हें ईमानदारी से प्रस्तुत करने की इच्छा।

फांसी दिवस पर

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।

मंगल पांडे : 1857 की क्रांति के दीप्तिमान नायक

29 मार्च, 1857। कलकत्ता से 22 किमी दूर भारत की सबसे बड़ी और प्लासी युद्ध के बाद सन् 1765 में स्थापित पहली सैन्य छावनी बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कम्पनी की बंगाल इंफेंट्री रेजीमेंट की 34वीं वाहिनी के सिपाही सुबह नियमित परेड के लिए मैदान में वर्दी पहने अपनी बंदूकों सहित तैयार खड़े हैं। नायक के आदेश पर परेड आरम्भ हुई। सिपाही कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाते हुए निश्चित सीमा तक परेड करते हुए आ-जा रहे हैं। सिपाहियों की गर्दनें तनी हुई और सिर ऊंचे हैं। पूरी देह में रक्त नसों में दौड़ रहा है। सिपाहियों के मुख मण्डल शौर्य एवं पराक्रम से दीप्तिमान हैं। किंतु आज सैनिकों का भाव और व्यवहार बिलकुल अलग सा है। लग रहा है कि जैसे उनके हृदयों में कुछ उबल रहा है। परेड को विश्राम दिया गया और सभी सिपाहियों को नये कारतूसों का वितरण शुरू हुआ। लेकिन यह क्या, एक सिपाही ने कारतूस लेने से स्पष्ट मना कर दिया। वह बोला, 'इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी है। हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा।' अन्य सिपाहियों ने भी साथ दिया। कारतूस वितरण करने वाले ने कड़क आवाज में पूछा, 'तुम्हारा नाम-परिचय क्या है?' वह युवा सिपाही उच्च स्वर में बोला, 'नाम मंगल पांडे। पिता दिवाकर पांडे, माता अभय रानी। जन्म तिथि 19 जुलाई, 1827 बलिया में। सेना में भर्ती सन् 1849 में।' इतना सुनकर कारतूस वितरण करने वाला अधिकारी काम बंद कर लेफ्टिनेंट बॉग के कक्ष की ओर बढ़ गया और सैनिक अपनी बैरकों की ओर।

हुगली नदी के सुरम्य प्राकृतिक तट पर स्थित ईस्ट इंडिया कम्पनी की बैरकपुर छावनी में उस दिन सुबह की इस घटना ने पूरे सैन्य अधिकारियों के कान खड़े कर दिए थे। समाधान हेतु उनमें विचार-विमर्श चल रहा था। इधर, सैनिक भी अपनी बैरकों में बैठे चर्बी वाले कारतूस प्रयोग न करने पर दृढ़ संकल्पित थे क्योंकि बंदूक की नली में कारतूस भरने से पहले उसका अगला सिरा दांत से काट बारूद नली में भरकर फिर कारतूस डालना होता था। गाय हिंदुओं के लिए पूज्या थी तो सुअर की चर्बी से मुस्लिम सैनिकों की भावना आहत थी। सैनिकों ने तय किया कि यदि अधिकारियों ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने का दबाव बनाया तो खुला विरोध करेंगे, बगावत होगी। मंगल पांडे के दिल-दिमाग में यह बात कुछ अधिक ही घर कर गई थी। उस शाम जब सूर्यदेव विश्राम हेतु पश्चिम के नील गगन के क्षितिज-पर्यंक पर गमन करने वाले थे, विहंग वृंद अपने नीड़ की ओर उड़ान भर रहा था, गायें रंभाती हुई बछड़ों को दुग्धपान कराने गोशाला की ओर दौड़ रही थीं, तभी उस गोधूलि बेला में मंगल पांडे भरी बंदूक लेकर बैरक से बाहर आया और साथी सिपाहियों को ललकारते हुए चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग के विरोध हेतु बाहर निकलने का आह्वान किया। सिपाही बाहर आ गये। घटनाक्रम की खबर अंग्रेजों के वफादार किसी सैनिक द्वारा नमक-मिर्च लगाकर तुरंत लेफ्टिनेंट बॉग तक पहुंची।

नाफरमानी को बगावत समझ लेफ्टिनेंट बॉग झटपट घोड़े पर सवार हो सिपाहियों की ओर बढ़ चला। शीघ्र ही पहुंचकर उसने देखा कि तीस वर्षीय सिपाही मंगल पांडे साथी सिपाहियों को कारतूस नहीं लेने के लिए मना कर रहा है, सिपाहियों में आक्रोश है। रोष से चेहरे तमतमा उठे हैं। लेफ्टिनेंट बॉग समझ गया कि यह तो खुला विद्रोह है, फिर भी अंदर से भयभीत उसने साहस बटोर कर आदेश दिया, 'सिपाहियों! बैरक में जाओ।' पर विरोध में एक साथ कई मुट्ठियां आकाश में तन गईं। बौखलाये बॉग की नजर नेतृत्व कर रहे सैनिक मंगल पांडे पर पड़ी और वह गरज कर बोला, 'तुम अपनी बंदूक और वर्दी जमा करो।' आदेश का कोई असर होता न देख, वह मंगल पांडे को पकड़ने को बढ़ा। किंतु मंगल पांडे ने फायर कर दिया। बॉग बाल-बाल बच गया, किंतु गोली घोड़े के पैर पर लगी और सवार सहित घोड़ा धराशायी हो गया। बॉग खड़ा हुआ और सिपाहियों को मंगल पांडे को पकड़ने का हुक्म दिया पर एक भी सिपाही आगे नहीं बढ़ा। क्रोधित लेफ्टिनेंट बॉग ने तलवार निकाल मंगल पांडे पर प्रहार किया। बचाव में मंगल पांडे ने भी तलवार से जोरदार हमला किया, बॉग के सीने से लहू की धार बह निकली। तब तक मेजर ह्यूसन अंग्रेज सैनिकों के साथ पहुंच गया जिसका स्वागत मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली ने किया। अब मंगल पांडे की तलवार का मुकाबला एक साथ दो तलवारों से हो रहा था। लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर ह्यूसन खून से लथपथ थे पर तलवारें भांज रहे थे, कि तभी मंगल पांडे ने उछलकर तलवार का जोरदार प्रहार किया किंतु अंग्रेजों के वफादार सैनिक शेख पलटू ने मंगल पांडे की कमर पकड़ ली। तब तक अन्य अंग्रेज सैनिकों का जत्था निकट आ पहुंचा। अपने को घिरा देख मंगल पांडे ने आत्म बलिदान हेतु स्वयं पर गोली मार ली, वह घायल होकर मां भारती की गोद में गिर पड़े। अंग्रेज सैनिकों ने मंगल पांडे को बंदी बना लिया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 अप्रैल, 1857 को कोर्टमार्शल हुआ और मंगल पांडे को मृत्युदंड दिया गया। फांसी की तारीख निश्चित की गई 18 अप्रैल। किंतु मेरठ, कानपुर, दिल्ली से आ रही बगावत की खबरों से परेशान अंग्रेजों ने तय तारीख से दस दिन पहले 8 अप्रैल, 1857 की प्रातः 5.30 बजे बैरकपुर छावनी में सिपाहियों के सामने घायल मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस दिन जब सूरज उगा तो अपनी किरणों का स्वर्णिम गुच्छ बलिदानी मंगल पांडे के चरणों में समर्पित कर अपनी श्रंद्धाजलि दी, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे को फांसी के बाद सामूहिक सजा के तौर पर पूरी 34वीं रेजीमेंट को भंग कर दिया गया

मंगल पांडे की स्मृति में भारत सरकार ने 5 अक्टूबर, 1984 को 50 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया, जिसे कलाकार सी.आर.पाकरसी ने डिजाइन किया था। बैरकपुर में बना मंगल पांडे का ओजमय समाधि स्थल दर्शनार्थियों में देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान का भाव भरते हुए देश के सर्वांगीण विकास का आह्वान कर रहा है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस

डॉ. परशुराम तिवारी

(लेखक स्वेच्छिक जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पूर्व सलाहकार हैं।)

बेहतर स्वास्थ्य के बिना कठिन है जीवन में आनंद

स्वतंत्रता के दशकों बाद भी हम अनेक जनस्वास्थ्य चुनौतियों से घिरे हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और अधिक जटिल हो गई हैं। रासायनिक उर्वरकों से उत्पादित खाद्यान्न, प्रसंस्कृत एवं डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का बढ़ता उपयोग, और सूचना क्रांति के माध्यम से प्राप्त भ्रमित एवं अपूर्ण जानकारी—ये सभी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनियंत्रित उपयोग भी कहीं न कहीं हमारी मौलिक सोच और जीवनशैली को प्रभावित कर रहा है। विचारणीय प्रश्न यह है कि- क्या हम गरीबी, टीबी, डेंगू, मलेरिया, दस्त, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप और साइलेंट हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटे बिना 'विश्व गुरु' बनने का दावा कर सकते हैं?

जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशी (आनंद), दोनों ही मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ 'अष्टांग हृदयम्' के अनुसार निरोगी जीवन हमारी दिनचर्या, आहार तथा त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) के संतुलन पर निर्भर करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भी स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने की अवस्था है। संक्षेप में, यह वह स्थिति है जहाँ शरीर, मन और आत्मा में संतुलन और सामंजस्य स्थापित हो। यदि यह संतुलन बना रहे, तभी मनुष्य वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है।

सरल शब्दों में, स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है।

आज की चुनौतियाँ

स्वतंत्रता के दशकों बाद भी हम अनेक जनस्वास्थ्य चुनौतियों से घिरे हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और अधिक जटिल हो गई हैं। रासायनिक उर्वरकों से उत्पादित खाद्यान्न, प्रसंस्कृत एवं डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का बढ़ता उपयोग, और सूचना क्रांति के माध्यम से प्राप्त भ्रमित एवं अपूर्ण जानकारी–ये सभी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का अनियंत्रित उपयोग भी कहीं न कहीं हमारी मौलिक सोच और जीवनशैली को प्रभावित कर रहा है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि–क्या हम गरीबी, टीबी, डेंगू, मलेरिया, दस्त, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप और साइलेंट हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटे बिना 'विश्व गुरु' बनने का दावा कर सकते हैं?

जब सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर हो, निजी अस्पतालों का खर्च आम नागरिक की पहुंच से बाहर हो, और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता निरंतर गिर रही हो–तब क्या समाज का बड़ा वर्ग वास्तविक खुशी या आनंद का अनुभव कर सकता है?

खुशी या आनंद क्या है?

रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने आनंद का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है- 'परहित सरिस धरम नहि भाई, पर पीड़ा सम नहि अधमाई॥' अर्थात, दूसरों का कल्याण करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म। व्यावहारिक जीवन में भी यह देखा गया है कि सच्ची खुशी त्याग, सेवा और परोपकार से प्राप्त होती है। जब हम दूसरों के जीवन में आनंद लाते हैं, तभी हमें वास्तविक संतोष और खुशी का अनुभव होता है।

इस प्रकार खुशी केवल क्षणिक सुख नहीं, बल्कि जीवन के प्रति संतोष, अर्थपूर्णता और मानसिक संतुलन का अनुभव है। स्वास्थ्य और खुशी के बीच गहरा संबंध है। अच्छा स्वास्थ्य खुशी को बढ़ाता है और खुशी बेहतर स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती है। इस प्रकार बेहतर स्वास्थ्य के बिना जीवन में आनंद की राह कठिन हो जाती है।

समाज में आनंद हेतु प्रयास

समाज में आनंद के स्तर को समझने और बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश देश का एकलौता राज्य है जहाँ विगत 10 वर्षों से राज्य आनंद संस्थान इस हेतु सक्रिय है। संस्थान का मानना है कि- 'नागरिकों की खुशहाली और परिपूर्ण जीवन के लिए आंतरिक एवं बाह्य संतुलन आवश्यक है। केवल भौतिक प्रगति से स्थायी प्रसन्नता संभव नहीं है। राज्य का समग्र विकास नागरिकों की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक उन्नति तथा प्रसन्नता पर निर्भर करता है।'

इस उद्देश्य से संस्थान ने अब तक हजारों आनंदक (वालंटियर) और प्रशिक्षकों को तैयार किया है तथा इस हेतु समय-समय पर विविध गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती रही हैं। तथापि, इन प्रयासों के ठोस परिणामों और प्रभावों का समग्र आकलन अभी अपेक्षित है।

मैदानी हकीकत क्या है?

भारत में खुशहाली के ठोस संकेतक अभी भी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, हाल ही में जारी वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार 147 देशों में भारत का स्थान 116वाँ है। जबकि फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। वहीं अमेरिका 23वें, इंग्लैंड 29वें, चीन 65वें और पाकिस्तान 104वें स्थान पर हैं। भारत में खुशहाली के निम्न स्तर के पीछे कई कारण हैं, जिनमें प्रति व्यक्ति आय का कम होना, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में कमी, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति, सामाजिक उदारता में कमी एवं लोगों में बढ़ता एकाकीपन प्रमुख हैं।

आगे की राह– कुछ अनुसंशायें

यदि देश में खुशहाली के स्तर को सुधारना है, तो सबसे पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बजट को लगभग 2 प्रतिशत बढ़ाकर दोगुना करना एवं सेवाओं की गुणवत्ता में ठोस सुधार लाना होगा। साथ ही मानव विकास से जुड़े सभी विभागों–जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आनंद संस्थान आदि के कार्यों की प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन में नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करनी होगी।

एक कल्याणकारी राज्य के लिए यह भी आवश्यक है कि वह नियमित रूप से मानव विकास प्रतिवेदन (Human Development Report) जारी करे, जिससे विकास और आनंद के बीच के संबंध को समझा जा सके और उसी के अनुरूप नीतियों का निर्माण किया जा सके।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतू परमार पहुंची नगरपालिका

कार्यालय पहुंचकर सौंपा आवेदन, प्रशासन ने उच्च स्तर से मांगा मार्गदर्शन

बैतूल। मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस की नीतू परमार और भाजपा की वर्षा गड़ेकर के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर आखिरकार विराम लग गया है। हाईकोर्ट ने नीतू परमार के पक्ष में निर्णय देते हुए उन्हें अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद मुलताई की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नीतू परमार कांग्रेस पदाधिकारियों व समर्थकों के साथ नगर पालिका कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने अध्यक्ष पद का प्रभार लेने की प्रक्रिया शुरू करते हुए प्रशासन को आवश्यक दस्तावेज सौंपे। कार्यालय पहुंचने पर नीतू परमार ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी को न्यायालय के आदेश की प्रति सौंपी। साथ ही उन्होंने औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपने की मांग की। परमार ने कहा कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार उन्हें तत्काल पदभार दिया जाना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस पार्षद अंजलि शिवहरे, वंदना साहू, शिव माहोरे सहित वरिष्ठ नेता किशोर सिंह परिहार, अरुण यादव, लोकेश यादव एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुमित शिवहरे समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नीतू परमार के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

प्रशासन ने मांगा उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन...

सीएमओ वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि उन्हें न्यायालय का आदेश और आवेदन प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है तथा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट ने नीतू परमार को वैध अध्यक्ष माना, लंबा कानूनी संघर्ष समाप्त

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर पिछले लगभग तीन वर्षों से चल रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में नीतू परमार के निर्वाचन को वैध ठहराते हुए उन्हें पुनः अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने की अनुमति दे दी है।

क्या मायने हैं इस फैसले के...

इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए गए विवादों का अंतिम निपटारा न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामले का शीघ्र समाधान संभव हो सका।

अंतिम निष्कर्ष

(1) नीतू परमार का चुनाव पूरी तरह वैध घोषित

(2) जिला न्यायालय का आदेश निरस्त

(3) लंबा कानूनी विवाद समाप्त

(4) मुलताई नगर पालिका को स्थायी नेतृत्व मिला

इनका कहना है –

मैं पहले भी सत्य के साथ थी और आज भी हूं। न्यायालय का यह निर्णय सत्य की जीत है। अब मेरी पहली प्राथमिकता नगर के विकास कार्यों को गति देना होगी।

– नीतू परमार

मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हूं और जहां तक इस फैसले के खिलाफ पुनः न्यायालय में जाने का सवाल है। भाजपा संगठन का जो भी आदेश होगा, वैसा निर्णय लिया जाएगा।

– वर्षा गडेकर
अध्यक्ष नगर पालिका मुलताई

क्या था पूरा विवाद ...

नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नीतू परमार और वर्षा गढ़ेकर के बीच विवाद शुरू हुआ था। चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते मामला पहले स्थानीय न्यायालय पहुंचा, जहां से हाईकोर्ट और अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा न्यायालयों के प्रमुख आदेश (टाइमलाइन)

13 जून 2023 – स्थानीय न्यायालय का फैसला
स्थानीय अदालत ने नीतू परमार का चुनाव निरस्त करते हुए पुनः चुनाव कराने के निर्देश दिए।

20 जून 2023 –प्रशासनिक निर्णय
राज्य शासन ने अंतरिम व्यवस्था के तहत वर्षा गढ़ेकर को अध्यक्ष नियुक्त किया।

15 जुलाई 2023 – हाई कोर्ट से राहत
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाकर नीतू परमार को पुनः पद पर बहाल कर दिया।

4 अक्टूबर 2023 – याचिका खारिज
हाई कोर्ट ने नीतू परमार की याचिका खारिज कर दी, जिससे मामला फिर पलट गया।

15 दिसंबर 2023 – सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्टे आदेश को निरस्त कर दिया।

5 फरवरी 2024 – संयुक्त सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की याचिकाओं को एक साथ सुनने का निर्णय लिया।

2024 –समयसीमा तय
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को तीन माह के भीतर अंतिम निर्णय देने के निर्देश दिए।

6 अप्रैल 2026 – अंतिम फैसला
हाई कोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए नीतू परमार के चुनाव को वैध घोषित कर दिया।

इस पूरे प्रकरण में अब तक करीब 8 प्रमुख न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेश पारित हुए, जिनमें विभिन्न स्तरों पर निर्णय बदलते रहे।

जिला किसान कांग्रेस पत्रकारवार्ता

गेहूं की खरीदी शीघ्र की जाए, खाद पर्याप्त उपलब्ध करें, अन्यथा 9 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय का घेराव

सोहागपुर। सोहागपुर के वाटिका ग्रार्डन परिसर में जिला किसान कांग्रेस की पत्रकार वार्ता नगर कांग्रेस के तत्वावधान में संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी, सोहागपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे पुष्पराजसिंह पटेल, पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय,केलू उपाध्याय, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर,शोभापुर सरपंच सुरेखा शाह,नगर किसान कांग्रेस अध्यक्ष गणेश अहिरवार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, हेमू कश्यप, पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष गजेन्द्र चौधरी, अजय ठाकुर आदि मंचासीन थे।

किसानों के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देरी कर रही है। इससे किसानों को मजबूरन अपनी फसल को कम दामों में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है।इससे किसानों को प्रति क्विंटल 300 से 400 रू. का नुकसान हो रहा है। आपने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर किसानों का गेहूं नहीं खरीद रही है। वह किसानों से गेहूं खरीदी में विलंब करना चाहती है ।क्योंकि सरकार किसानों का पूरा गेहूं ना खरीद कर मात्र 25 प्रतिशत ही गेहूं खरीदना चाहती है। वहीं चने की खरीदी भी अभी प्रारंभ नहीं की गई है ।चने की खरीदी आज से किया जाना था। लेकिन सोहागपुर में चना खरीदी का केंद्र ही नहीं बनाया गया है ।इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चने की पैदावार की जाती है। श्री चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार मूंग को जहरीली मूंग का तमगा लगाकर मूंग को ना खरीदने की ओर इशारा कर रही है। इस क्षेत्र में उड़दा में नहीं बोया जाता । जबकि मूंग की फसल 50 से 55 दिन में आ जाती है। वहीं उड़द की फसल 90 दिन में पैदा होती है। आपने आगे कहा कि सरकार किसानों किसने की नरवाई जलाने को लेकर एफआईआर दर्ज कर रही है। बिना कोई उपाय बताए , बिना किसी योजना के सरकार किसानों पर दबाव बना रही है । इससे किसानों को मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है।। आपने सरकार को सुझाव दिया कि किसानों के साथ आपसी बातचीत करके उनके सुझावों को लेकर जो आवश्यक और कारगर उपाय बताकर किसानों का सहयोग प्राप्त कर सकती है। आपने तत्काल किसानों की समस्याओं का निदान नहीं किया तो 9 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुरम का घेराव करने की चेतावनी दी। श्री अनिल ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जो नई खाद्य वितरण प्रणाली लागू की है। यह इससे किसानों को फायदा देने के बजाय ज्यादा परेशानी दे रही है । किसानों को दूर-दूर के सेंटरों पर जाकर खाद लेना पड़ रहा है। इससे खाद की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस परेशानी के कारण किसान महंगी खाद लेने की बजाय मजबूरी में ब्लैक में खाद खरीद लेगा। जो काम सरकारी खाद की तुलना में कम कीमत और समय पर जरूरत के अनुसार उतनी मात्रा में खाद्य प्राप्त हो जाएगा । आपने सरकार से आग्रह किया है कि खाद्य का समुचित उपाय करके किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी ने क्षेत्र के किसानों से एकजुटता का आग्रह किया है। ताकि प्रदेश सरकार किसानों को लिए सकारात्मक कदम उठाए। इस अवसर पर पूर्व पार्षद मोहन कहार, वकील कार्तिक शर्मा, वकील देवांशू शर्मा,नीरज चौधरी सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे।

खेत से पानी की मोटर चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। आमला पुलिस ने खेत से पानी की मोटर चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.20 लाख का मशरूका बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 अप्रैल की रात्रि लगभग 11.30 बजे से 12.30 बजे के मध्य फरियादी सुदामा सिंह पिता मनोहर सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम खरपड़ाखेड़ी के खेत (ग्राम सेमरियाजोशी) में बने टीनशेड कमरे का अज्ञात आरोपी द्वारा ताला तोड़कर अंदर रखी ओपल व्हील पानी की मोटर (कीमत 25,000)

चोरी कर ली गई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना आमला में धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आमला पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अमित पिता पंचम मालवीय, (35) निवासी वार्ड नं. 31 शोभापुर मैगजीन कॉलोनी एवं राजेन्द्र सिंह पिता सूपसिंह रघुवंशी (21) निवासी वार्ड नं. 31 शोभापुर मैगजीन कॉलोनी, पाथाखेड़ा थाना सारणी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक गोल्डन रंग की टीवीएस ज्यूपिटर स्कूटी कीमत 90,000 एवं एक ओपल व्हील मोटर कीमत 25,000 तथा चोरी में प्रयुक्त औजार (13 पट्टी पाना, 05 रिंग पाना, 01 कैंची कटर, 01 आरी, 01 हथौड़ी, 01 लीवर) कुल 1,20,000 का माल बरामद किया गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक रविकांत डेहरिया, सउनि रामेश्वर सिंह, प्रधान आरक्षक नीलेश सोनी, प्रधान आरक्षक कमलेश धुर्वे, आरक्षक तिलक कोड़ापे, आरक्षक विवेक पाल एवं आरक्षक नागेन्द्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

बेल नदी उद्गम पर जल स्रोत सेवा समागम, जल संरक्षण का दिया संदेश

बैतूल। बेल नदी के उद्गम स्थल बेलमंडई (पंखा) सरोवर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वितीय चरण अंतर्गत जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, बैतूल द्वारा किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उद्गम स्थल का पूजन मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) मोहन नागर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने उद्गम स्थल पर श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया तथा जल संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। यह आयोजन नवांकुर संस्था, माँ रेणुका पर्यावरण विकास

समिति (बोरी खुर्द), अभिनव समाज कल्याण संगठन, तरुण शक्ति समिति एवं डॉ. जगन्नाथ यदुवंशी आरोग्य वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर नदी अनुभूति, उद्गम क्षेत्र की साफ-सफाई, नागदेव पूजन, बरगद, पीपल एवं बेल जैसे पवित्र वृक्षों का पूजन, मानव श्रृंखला निर्माण एवं श्रमदान जैसी गतिविधियों के माध्यम से जनजागरूकता का संदेश दिया गया। साथ ही जल मंदिर (प्याऊ) का शुभारंभ भी किया गया। जल चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री नागर ने कहा कि नदियों की स्वच्छता और सतत प्रवाह धरती के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर में रक्त की शुद्धता आवश्यक होती है, उसी प्रकार नदियों का स्वच्छ और अविरल रहना जरूरी है। उन्होंने जल संरक्षण के विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा करते हुए स्थानीय समुदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में जिला समन्वयक प्रिया चौधरी ने जल और प्रकृति के बीच संबंध को स्पष्ट करते हुए जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

टेक्नोलॉजी और टीमवर्क का शानदार परिणाम

जनवरी 2026 से मार्च तक बरामद किये 100 मोबाइल

बैतूल। साइबर सेल एवं जिले के थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुम हुए 635 मोबाइल फोन को बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस दौरान पुलिस ने करीब 80 लाख के मोबाइल फोन वापस किये है। दरअसल पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के मार्गदर्शन में पुलिस ने यह कार्रवाही की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा गुम मोबाइल फोन की खोज एवं बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। पुलिस ने वर्ष 2026 जनवरी से मार्च माह तक कुल 100 गुम मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख है। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 635 गुमशुदा मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख बरामद किए जा चुके हैं। जिनमें से 535 से अधिक मोबाइल फोन लगभग 71 लाख मूल्य सत्यापन उपरांत उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाए गये है।

विभिन्न राज्यों एवं जिलों से ट्रैक कर प्राप्त किये मोबाइल– पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन देश के विभिन्न राज्यों एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलो से ट्रैक कर प्राप्त किए गए हैं। जिनमें सैमसंग, वनप्लस, मोटोरोला, वीवो, ओप्पो, रेडमी एवं रियलमी कंपनियों के स्मार्टफोन शामिल हैं। इन मोबाइल फोन को छात्र-छात्राओं, मजदूरों, किसानों,

गृहणियों सहित विभिन्न वर्गों के नागरिकों को सुपुर्द किया गया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी लौट आई और पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ।

इनकी रही सराहनीय भूमिका– इस कार्य में साइबर सेल टीम उप निरीक्षक अश्विनी चौधरी, उप निरीक्षक नवीन सोनकर, आर. राजेंद्र धाडसे, आर. बलराम राजपूत, आर दीपेन्द्र सिंह, आर पंकज नरवरिया,आर सचिन हनवते एवं थाना बोरदेही से आर. मनोज पाल, आर. सचिन दीवान, थाना आमला से आर.जितेंद्र, थाना भैंसदेही से आर नारायण जाट, थाना झल्लार से आर. हर्षवर्धन एवं थाना आठनेर से आर.कंचन चौरे का विशेष योगदान रहा।

मोबाइल गुम होने की तत्काल कराये शिकायत दर्ज– बैतूल पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाता है, तो तत्काल नजदीकी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराएं एवं उसकी प्रति प्राप्त करें। अपने मोबाइल नंबर का सिम पुनः जारी कराएं। 24 घंटे पश्चात सीईआईआर पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करें। उक्त प्रक्रिया अपनाने से गुमशुदा मोबाइल फोन की ट्रैकिंग एवं बरामदगी में अत्यधिक सफलता मिल रही है। साइबर सेल एवं थाना पुलिस की संयुक्त टीम आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे बड़ी संख्या में मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाए जा रहे हैं।

शराब दुकानों की नीलामी फेल, आबकारी अधिकारी निलंबित

बैतूल। बैतूल में शराब दुकानों के निष्पादन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी आयुक्त ग्वालियर दीपक कुमार सक्सेना ने जिला आबकारी अधिकारी अंशुमन चिढ़ार को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वर्ष 2026-27 के लिए शराब दुकानों की टेंडर प्रक्रिया में अपेक्षित परिणाम न मिलने और शासन के राजस्व हित प्रभावित होने के कारण की गई है। जानकारी के अनुसार, जिले में कुल 61 शराब दुकानें हैं, जिनमें से 8 दुकानें अब तक नीलाम नहीं हो सकी हैं। इनमें बैतूल बाजार की दो दुकानें, बैतूल गंज, आमला बस स्टैंड, भैंसदेही की दो दुकानें, सारणी नंबर-1 और बगडोना शामिल हैं। इन दुकानों की कीमत अत्यधिक होने के कारण ठेकेदारों ने इनमें रुचि नहीं दिखाई। बताया जा रहा है कि पहले दुकानों की नीलामी समूह बनाकर की गई थी, लेकिन समूह निर्धारण में गड़बड़ी सामने आई। कई दुकानों को 30-30 किमी दूर तक जोड़कर समूह बनाए गए थे, जिससे ठेकेदारों के लिए उनका संचालन व्यावहारिक नहीं रहा। बाद में समूह तोड़ने पर छोटी दुकानें तो नीलाम हो गईं, लेकिन महंगी दुकानें अब भी खाली पड़ी हैं। इससे राजस्व का नुकसान होने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में अंशुमन चिढ़ार का मुख्यालय संभागीय कार्यालय भोपाल निर्धारित किया गया है।

वार्ड एवं पंचायत कमेटी कांग्रेस का सशक्त आधार बनेगी : निलय डागा

जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरे पदाधिकारी, संगठन मजबूत करने का लिया संकल्प

बैतूल। बैतूल विधानसभा में कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों और मंडलम अध्यक्षों की बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय विनोद डागा ने साफ कहा कि आने वाले समय में पार्टी की असली ताकत वार्ड और पंचायत कमेटियां होंगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी पत्र सौंपते हुए उन्हें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया और संगठन को गांव-गांव तक मजबूती देने का आह्वान किया। बैठक में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों और मंडलम अध्यक्षों का सम्मान किया गया और उन्हें औपचारिक रूप से जिम्मेदारी पत्र सौंपे गए। इस दौरान श्री डागा ने कहा कि संगठन में पद केवल पहचान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर

पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना होगा और संगठन को मजबूत बनाना होगा।

जमीनी ढांचे को मजबूत करने की रणनीति– श्री डागा ने बैठक में वार्ड कमेटी और पंचायत कमेटियों के गठन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि यही इकाइयां कांग्रेस का वास्तविक आधार बनेंगी और इन्हीं के जरिए पार्टी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करेगी। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन कमेटियों का गठन कर उन्हें सक्रिय किया जाए, ताकि संगठन हर स्तर पर मजबूत हो सके।

9 अप्रैल को धरना प्रदर्शन का आह्वान– बैठक में किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने अपनी रणनीति स्पष्ट की। निलय डागा ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 9 अप्रैल को किसानों के समर्थन में होने वाले धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान करते कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है और इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाना जरूरी है। बैठक में आदिवासी कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक अर्चना पोरते, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश साहू, संगठन महामंत्री ब्रजभूषण पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार चौबे, मनोज कालू आहूजा, सत्यप्रकाश लल्ला पटेल रावत, पूर्व अध्यक्ष मोनू बडोनिया, प्रशांत राजपूत, प्रभारी लवलेश बब्बा राठौर, सुभाष पांडे सहित वरिष्ठ कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

राज्य अतिथि के रूप में बैतूल पहुंचेंगे सुधांशु महाराज, भक्ति सत्संग को लेकर शहर में उत्साह

बैतूल। पुलिस परेड ग्राउंड में 9 से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले विराट भक्ति सत्संग को लेकर शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। परमपूज्य सुधांशुजी महाराज 9 अप्रैल को राज्य अतिथि के रूप में शहर में पधारेंगे। पुलिस ग्राउंड में होने वाले इस आयोजन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में प्रवचन, संवाद और 12 अप्रैल को निशुल्क गुरु दीक्षा का आयोजन भी होगा। मंगलवार 7 अप्रैल को आयोजन स्थल पर पत्रकार वार्ता में आयोजन समिति के डॉ विनय सिंह चौहान ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि यह आयोजन जिले का एक बड़ा आध्यात्मिक समागम बनने जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। डॉ. विनय चौहान ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते बताया कि परमपूज्य सुधांशु महाराज का आगमन 9 अप्रैल को दोपहर 12 बजे होगा। उसी दिन शाम 4:30 बजे से सत्संग का विधिवत शुभारंभ होगा। तीन दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में भक्ति, प्रवचन और आध्यात्मिक चिंतन का संगम देखने को मिलेगा।

निशुल्क गुरु दीक्षा का विशेष अवसर– कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण 12 अप्रैल को दोपहर 12 बजे आयोजित होने वाली निशुल्क गुरु दीक्षा होगी। आयोजन समिति के अनुसार, यह अवसर श्रद्धालुओं हेतु आध्यात्मिक जीवन की नई शुरुआत का मार्ग खोलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग दीक्षा लेने पहुंचेंगे।

हर दिन दो सत्रों में होंगे प्रवचन– 10 से 12 अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह 9 से 11.30 बजे और शाम 4.30 से 7.00 बजे तक सत्संग व प्रवचन होंगे। इन सत्रों में जीवन, धर्म और नैतिक मूल्यों पर गहन मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे श्रद्धालु अपने जीवन को नई दिशा दे सकेंगे।

10 अप्रैल को सुबह एक विशेष सत्र रखा गया है, जिसमें आठवीं कक्षा से ऊपर के स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया है। इस सत्र में महाराज बच्चों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे और उन्हें सही मार्गदर्शन देंगे। यह सत्र शिक्षा और संस्कार दोनों के लिहाज से खास माना जा रहा है।

विशाल पंडाल और विशेष बैठने की व्यवस्था– आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि सत्संग हेतु 100 ×250 फीट का विशाल पंडाल तैयार किया है। इसमें बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अलग से बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि सभी श्रद्धालु सहज और व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। विश्वकर्मा मंदिर गंज में उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो और वे पूरी तरह भक्ति में लीन रह सकें। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु एंबुलेंस भी तैनात रहेगी। पत्रकार वार्ता में डॉ. विनय सिंह चौहान, अशोक हिरानी, एचएस सलाम, एलएन राठौर, शैलेंद्र राठौर, कविता धोटे, वर्षा बारस्कर, सुरेंद्र कुशवाहा, बलवीर मालवीय, राजेंद्र महाले, हर्ष मालवीय, विजय बागरी सहित आयोजन समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से दिया जल गंगा संवर्धन अभियान का संदेश

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद नर्मदा पुरम के द्वारा कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशन में समस्त जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं एवं उनके द्वारा अपने प्रयोगशाला ग्राम में कई तरह की जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए छात्रों के द्वारा समस्त जिले में सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है इसी क्रम में रविवार मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम की नर्मदा पुरम की क्लास में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से जल संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया इस अवसर पर जन अभियान परिषद के परामर्शदाता, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि उपस्थित रहे इस समस्त आयोजन में परामर्शदाता नीरज चतुर्वेदी, अभिषेक सैनी, विनीत यादव, राम मीना, राजेंद्र कुशवाहा के महत्वपूर्ण भूमिका रही। नवांकुर संस्था स्मार्ट एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा पांच सर्वश्रेष्ठ विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए।

पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिए किया गया टीकाकरण

सीहोर (निप्र)। वेटरनरी विभाग द्वारा जिले के ग्राम नीमटोन में पशुओं को खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) रोग से सुरक्षित रखने के लिए पशुओं का एफएमडी टीकाकरण किया गया तथा रोग की निगरानी के उद्देश्य से प्री-वैक्सीनेशन सैंपल भी एकत्रित किए गए। विभागीय टीम ने पशुपालकों को पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और समय-समय पर टीकाकरण कराने की सलाह दी। खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है, जो गाय, भैंस, बकरी एवं अन्य खुर वाले पशुओं को प्रभावित करता है। इस रोग से पशुओं में बुखार, मुंह में छाले, खुरों में घाव तथा दूध उत्पादन में कमी जैसी समस्याएं होती हैं। एफएमडी वैक्सीनेशन इस रोग से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है, जिससे पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है। नियमित टीकाकरण से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से भी बचाया जा सकता है।

जल गंगा संवर्धनअभियान के तहत निर्मित खेत तालाब बन रहा आर्थिक समृद्धि का आधार

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले की सिलवानी जनपद पंचायत की सिंहपुरी उचेरा ग्राम पंचायत निवासी हितग्राही किसान श्री रामप्रसाद अहिरवार के खेत में जल गंगा संवर्धन अभियान -2025 अंतर्गत बनाया गया खेत तालाब श्री रामप्रसाद की आर्थिक समृद्धि का आधार बन रहा है। खेत तालाब बनने से पहले श्री रामप्रसाद अपनी तीन एकड़ असिंचित भूमि में सिंचाई के लिए पूर्णतः बारिश पर ही निर्भर थे और बमुश्किल एक फसल ही ले पाते थे ! जिससे उन्हें बहुत कम आय होती थी। लेकिन वर्ष 2025 में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उनके खेत में 1.87 लाख रुपए लागत से खेत तालाब का निर्माण किया गया। जिसमें बारिश का पानी एकत्रित होने से अब वह दो फसल ले रहे हैं। इससे उनकी आमदनी में वृद्धि हुई तथा परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है। हितग्राही श्री रामप्रसाद बताते हैं कि 'तालाब बनने के बाद मेरे खेतों में पूरे वर्ष पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है, अब दो फसलें लेकर आमदनी बढ़ी है और जीवन में स्थायित्व आया है।' यह कार्य जल संरक्षण, कृषि उत्पादकता वृद्धि और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कोई भी प्रभावित किसान फसल सर्वे में न छूटे, क्षति की रिपोर्ट बीमा पोर्टल पर भी दर्ज कराएं

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में ओलावृष्टि एवं वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे राजस्व, कृषि, पंचायत एवं उद्यानिकी विभाग के संयुक्त दल द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट ने मुलताई क्षेत्र के पबोट नंबर 7065514447 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस एप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए किसान प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर लॉगिन करते हुए अपनी क्षति का विवरण दर्ज करें। यदि सूचना दर्ज करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसल क्षति की सूचना अनिवार्य रूप से 72 घंटे के भीतर दर्ज कराएं, ताकि समय पर राहत की कार्यवाही सुनिश्चित की ज्रभावित ग्रामों का दौरा कर फसल क्षति का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम मुलताई श्री राजीव कहार, तहसीलदार श्री संजय बैरिया, सहायक यंत्री कृषि डॉ. प्रमोद मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर श्रीमती जाट ने ग्राम परमंडल, करपा एवं चंदौरा में किसानों के खेतों में पहुंचकर गेहूं, गोभी, टमाटर एवं प्याज की फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से संवाद कर आश्वस्त किया कि कोई भी प्रभावित किसान सर्वे से नहीं छूटेगा। राजस्व, कृषि एवं पंचायत विभाग के दल द्वारा व्यवस्थित सर्वे कर फसल क्षति राहत की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल क्षति की सूचना बीमा कंपनी के निर्धारित नंबर एवं पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।

कृषक फसल क्षति की सूचना दें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बैतूल जिले के जिन किसानों की फसल जलभराव या अतिवृष्टि से प्रभावित हुई है , वे अपनी फसल क्षति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 14447, व्हाट्सएप चैटा सके।

माखन लाल चतुर्वेदी ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य किया :मंत्री सारंग

मंत्री श्री सारंग माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती एवं माखन नगर गौरव दिवस के कवि सम्मेलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए

नर्मदापुरम (निप्र)। राष्ट्रकवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने साहित्य की पूजा एवं सेवा करते हुए समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। हर कालखंड में साहित्य ने राजा महाराजाओं से लेकर समाज के हर तपके से लेकर सरकार तक को सही दिशा दिखाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है। इसके अग्रसर के रूप में राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने भी अपनी कविताओं एवं साहित्य के माध्यम से तत्कालीन समाज को जागरूक करने का कार्य किया था। उक्त बात प्रदेश के सहकारिता विभाग एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने माखन नगर में आयोजित राष्ट्रकवि पंडित श्री माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती एवं माखन नगर गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में कहीं। मंत्री श्री सारंग ने कवि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहां की महान राष्ट्रकवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का योगदान समाज एवं भारतवर्ष को एक करने में रहा है, उन्होंने पंडित चतुर्वेदी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। मंत्री श्री सारंग ने कवि सम्मेलन में अपने कविताओं से लोगों का मनोरंजन करने वाले सभी कवियों को भी शुभकामनाएं दी एवं उनका आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अपने देश एवं समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ लगाएंगे और साहित्य हमेशा की तरह इस देश और समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य हमेशा की तरह करता रहेगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, विधायक सोहागपुर श्री विजयपाल सिंह, श्रीमती प्रीती शुक्ला, अपर कलेक्टर श्री अनिल जैन, एसडीएम श्री जय सोलंकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण एवं अधिकारी गण तथा बड़ी संख्या में आम जनता उपस्थित रहे।देर रात तक आयोजित कवि सम्मेलन में हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा, श्री शशिकांत यादव, श्री नीलोत्पल मृणाल, रमेश विश्वहार, दिनेश देसी, अंकित सिंह, शशि भूषण सिंह ने भी कविता पाठ किया।

असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना

नर्मदापुरम (निप्र)। असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियों (एसडीएम) को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी एसडीएम अपने-अपने अनुविभाग क्षेत्रों में शीघ्रता से सर्वे कार्य प्रारंभ कर ओलावृष्टि एवं वर्षा से हुई फसल क्षति तथा अन्य प्रकार के नुकसान का विस्तृत आंकलन करें। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी एसडीएम इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर संपादित करते हुए निर्धारित समय सीमा में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि प्रभावित किसानों एवं नागरिकों को शासन की ओर से आवश्यक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराई जा सके।

ई-उर्वरक वित्तरण प्रणाली से उर्वरक वितरण नही करने वाले 11 विक्रेताओं पर की गई कार्यवाही

02 के लाइसेंस निलंबित, 09 को कारण बताओ नोटिस जारी

सीहोर (निप्र)। कृषि विभाग द्वारा 01 एवं 02 अप्रैल के बीच ई-विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरक विक्रय नही करने वाले जिले के 11 विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई है। इसमें 09 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओं जारी कर 02 उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित किये गये है। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार किसानों को सुगम उर्वरक वितरण के लिए प्रदेश के साथ ही जिले में ई-उर्वरक वित्तरण प्रणाली लागू हो चुकी है। शासन द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि उर्वरक का वितरण ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए। कृषि विभाग द्वारा जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को पुनः सूचित किया गया हैं कि किसी भी परिस्थिति में ई-विकास प्रणाली से बाहर उर्वरक विक्रय न करें। यदि कोई उर्वरक विक्रेता सूचना के उपरांत भी ई-विकास प्रणाली से बाहर उर्वरक विक्रय करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

ई-टोकन से खाद वितरण में लापरवाही पर कलेक्टर ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आमला को किया निलंबित

बैतूल (निप्र)। प्रदेश में उर्वरक वितरण को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ई-टोकन प्रणाली लागू की गई है। शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2026 से बिना ई-टोकन के उर्वरक विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी किया गया है। इसके बावजूद विकासखंड आमला में 7 खुदरा विक्रेताओं एवं 3 सहकारी समितियों द्वारा 42.805 मीट्रिक टन उर्वरक का विक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाना सामने आया है। यह स्थिति उर्वरक वितरण व्यवस्था में निगरानी की गंभीर कमी और लापरवाही को दर्शाती है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने उप संचालक कृषि के प्रतिवेदन के आधार पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आमला श्री गोपाल साहू को निलंबित कर दिया है। शासन निर्देशों की अवहेलना एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत कदाचार मानते हुए, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की गई है। निलंबन अवधि के दौरान श्री साहू को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि अनुभाग बैतूल नियत किया गया है।

ई-टोकन से खाद वितरण में लापरवाही पर 2 कैडर प्रबंधक भी निलंबित

इसी क्रम में ई-टोकन प्रणाली के तहत खाद वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी के निर्देश पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बैतूल के अंतर्गत अंधरिया एवं डगरिया के दो कैडर प्रबंधकों को भी निलंबित किया गया है। साथ ही जिले की सभी सहकारी संस्थाओं एवं निजी प्रतिष्ठानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उर्वरक का वितरण केवल ई-टोकन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा तथा उनके मुख्यालय नियमानुसार निर्धारित किए गए हैं।

जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत चित्रकला एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता कराई की गई

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की सीएमसीएलडीपी की कक्षा में शासकीय महाविद्यालय में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। जिसमें जन अभियान परिषद के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विकासखंड समन्वयक श्री नरेन्द्र देशमुख ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख जन आंदोलन है, जो 19 मार्च से 30 जून 2026 तक संचालित है। इस अभियान का उद्देश्य तालाबों, कुओं, और बावड़ियों का कायाकल्प करना, नदियों को साफ करना और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है। यह जनभागीदारी से भू-जल स्तर बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जन अभियान परिषद के विद्यार्थियों ने 'जल ही जीवन है' एवं ' जल संरक्षण' के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चित्रकला एवं रैली के माध्यम से आमजन तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया गया।कार्यक्रम में विकासखण्ड समन्वयक नरेंद्र देशमुख, डॉ आई.एस. कनेस, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि एवं पार्षद प्रतिनिधि सुरेश यादव, हरीश नामदेव, मनीष चतुर्वेदी, विपिन यादव, नीतिराज सिंह यादव, नीरज चतुर्वेदी, परामर्शदाता हर्ष तिवारी, राकेश कीर, पूनम मीना, मनीष यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

'सेवा ही साधना: नर्मदा तट पर जागृत हुआ जनचेतना का दीप '

गुंजारी संगम बना आस्था, श्रम और संकल्प का जीवंत प्रतीक

संत दादा गुरु और प्रहलाद पटेल ने किया स्वच्छता एवं संगम का निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। बुधनी की पावन धरा पर स्थित गुंजारी नर्मदा संगम घाट आज पुनः उस दिव्य अनुभूति का साक्षी बना, जहां श्रद्धा और सेवा एकाकार होकर जनचेतना का नया इतिहास रचती दिखाई दी। मां नर्मदा की शांत, कल-कल बहती धारा के सान्निध्य में जब जनप्रतिनिधि, संत और आमजन एक साथ श्रमदान में जुटे, तो वह दृश्य केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का सजीव प्रतीक बन गया। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग के माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल का यह पुनः आगमन केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने स्वयं श्रमदान कर यह स्पष्ट किया कि सच्चा नेतृत्व वही है, जो अपने आचरण से प्रेरणा देता है। उनके द्वारा किया गया श्रमदान जनसामान्य के लिए एक सशक्त संदेश बनकर उभरा। इस पावन अवसर पर नर्मदा परिक्रमा के तपस्वी, पूज्य दादा गुरु जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया। चार बार नर्मदा परिक्रमा पूर्ण कर चुके और केवल नर्मदा जल का सेवन करने वाले संत का संगम पर आगमन मानो स्वयं मां नर्मदा का आशीर्वाद प्रतीत हुआ। दादा गुरु जी महाराज ने संगम के समग्र विकास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे केवल एक भौतिक स्थल नहीं, बल्कि साधना, आत्मशुद्धि और आंतरिक जागरण का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि नदियां केवल जलधाराएं नहीं, बल्कि जीवन की आधारशिला हैं, जिनकी पवित्रता बनाए रखना हम सभी का धर्म है।साथ ही उन्होंने 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार, मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं जनभागीदारी के संयुक्त प्रयासों से इस प्राचीन धरोहर को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जो वर्षों से उपेक्षित एवं आच्छादित रही थी। आज उसी प्राचीन घाट पर जिस प्रकार स्वच्छता और विकास के कार्य गति पकड़ रहे हैं, वह वास्तव में अनुकरणीय है और अन्य स्थानों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। मंत्री श्री पटेल ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि नदियों का संरक्षण केवल शासन का दायित्व नहीं, बल्कि समाज की सामू चेतना का दर्पण है। उन्होंने स्वच्छता को अभियान से आगे बढ़ाकर जीवन का संस्कार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करेगा, तभी स्थायी परिवर्तन संभव हो सकेगा। उन्होंने संगम स्थल पर चल रहे स्वच्छता एवं संरक्षण कार्यों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि इस पावन स्थल का विकास निरंतर और सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता रहे। गुंजारी नर्मदा संगम घाट पर आज का यह आयोजन प्रशासन, आध्यात्म और जनसहभागिता का अद्भुत संगम बन गया। श्रमदान करते हाथ, संतों का आशीर्वाद और जनसमूह की सक्रिय भागीदारी–इन सभी ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि जब सेवा को साधना का रूप मिलता है, तब परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। मां नर्मदा की पावन धारा के साक्ष्य में लिया गया यह संकल्प केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुंदर और संस्कारित धरोहर का वचन है। यह आयोजन हमें यह भी स्मरण कराता है कि प्रकृति की सेवा ही सच्ची पूजा है और जनसहभागिता ही उसका सबसे प्रभावी मार्ग है।

शादी के बाद भी थे ब्वॉयफ्रेंड से संबंध

पति को भनक लगी तो प्रेमी ने पत्थर से कुचल दिया सर, अंधे कत्ल का खुलासा

मैहर (नप्र)। मध्यप्रदेश के मैहर जिले में अमरपाटन थाना के औद्योगिक क्षेत्र पडक्का में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 23 वर्षीय राजभान कोल की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के पुराने प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।

घर से निकला फिर नहीं लौटा वापस

घटना की शुरुआत 3 अप्रैल की शाम से हुई, जब मौहरिया-जगन्नाथ निवासी राजभान कोल (23) किसी का फोन आने पर घर से निकला और वापस नहीं लौटा। अगले दिन गांव से करीब एक किलोमीटर दूर पडक्का इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी लाश मिली। राजभान के चेहरे और गले पर गहरे घाव थे, जिससे साफ था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है।

शादी के बाद भी जारी था इश्क

पूछताछ में मुख्य आरोपी दिलीप पटेल ने जो बताया वह हैरान करने वाला था। पूछताछ में दिलीप ने पुलिस को बताया कि दिलीप और साधना का प्रेम-संबंध शादी से पहले का था, जो शादी के बाद भी छुप-छुपकर जारी रहा। हाल ही में राजभान को अपनी पत्नी और दिलीप के रिश्ते पर शक होने लगा था, जिससे उनके मिलने-जुलने में बाधा आ रही थी। दिलीप ने राजभान को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त जितेन्द्र उर्फ बिज्जू, करण केवट और दो अन्य के साथ मिलकर प्लान बनाया।

मनोवैज्ञानिक पूछताछ ने खोला राज- अमरपाटन थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने जब मृतक की पत्नी साधना कोल और परिजनों से पूछताछ की, तो प्रेम प्रसंग का सुराग हाथ लगा। इसी आधार पर पुलिस ने दिलीप पटेल उर्फ कल्लू को हिरासत में लिया। पहले तो दिलीप पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से सख्ती बरती गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

शराबी पार्टी कर उतारा मौत के घाट- आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए राजभान को ही मोहरा बनाया। 3 अप्रैल को करण केवट ने राजभान को फोन कर पडक्का बुलाया। वहां सभी ने साथ बैठकर जमकर शराब पी। जैसे ही राजभान नशे में धुत हुआ, आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले राजभान को बेदम पीटा, फिर भारी पत्थर से उसका सिर कूच दिया। मौत पक्की करने के लिए टूटी हुई कांच की बोतल से उसका गला रेत दिया गया।

दो गिरफ्तार, तीन अब भी फरार- पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलीप पटेल और उसके साथी जितेन्द्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जब तीन फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं

- दतिया में चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार

भोपाल (नप्र)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती से जुड़े मामले में मंगलवार को अहम सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल भारती को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

राजेंद्र भारती को हुई है तीन साल की सजा- दरअसल, राजेंद्र भारती ने ग्रामीण विकास बैंक घोटाला मामले में अपनी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की हैं। 1 अप्रैल को दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है।

उपचुनाव की घोषणा नहीं कराएं

इसके अलावा, राजेंद्र भारती ने एक और याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है कि वह दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा न करे। यह सीट उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। हालांकि, अदालत ने इस मांग पर भी फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई और चुनाव प्रक्रिया जारी रखने पर रोक से इनकार कर दिया।

एमपी सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से उनकी याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने अपनी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी। साथ ही, अदालत ने उस अलग याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें भारती ने अपनी सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की लेकिन कोर्ट ने इस पर अभी कोई तत्काल राहत नहीं दी है।

सीएम ने की सुगम संपर्कता परियोजना की समीक्षा

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक करें उपयोग : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए ड्रोन का उपयोग हो। सिपरी साफ्टवेयर न सिर्फ डीपीआर तैयार करने की दृष्टि से उपयोगी है बल्कि सड़क के साथ पुल-पुलियों की आवश्यकता दर्शाने में भी इसका उपयोग हो रहा है। सड़क निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग शुरू करना सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को समत्व भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सुगम संपर्कता परियोजना संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि गत माह शुरू किए गए राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान की विभागीय स्तर पर प्रति सप्ताह समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक बगिया मां के नाम अंतर्गत की गई गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि परियोजना में प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा तथा 100 से अधिक आबादी वाले मजरों-टोलों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती दीपाली रस्तोगी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परियोजना की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि परियोजना में सड़कों का निर्माण मनरेगा अर्थात वीबी-जी-राम-जी योजना में से करवाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की प्रत्येक जनपद पंचायत तीन करोड़ तक की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी। सुगम संपर्कता परियोजना के माध्यम से गांवों, ग्राम पंचायतों को दोहरी संपर्कता प्रदान की जाएगी।

- गाँव परस्पर जुड़ेंगे तो सुगम हो जाएगी आवागमन सुविधा
- सुगम संपर्कता परियोजना में मजरों-टोलों और सांदीपनि स्कूलों तक बनेंगी सड़कें
- प्रत्येक जनपद पंचायत 3 करोड़ रुपए की दे सकेगी स्वीकृति

पूर्व से निर्मित सड़कों की जियो इंवेंट्री- सुगम संपर्कता परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें पूर्व में बनी सड़कों की रिम्स पोर्टल के माध्यम से जियो-इंवेंट्री की जा रही है। इससे नई सड़कों के चयन में दोहराव की स्थिति नहीं बनेगी। जियो इंवेंट्री में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, पीएमजीएसवाय, मुख्य जिला सड़क और संपर्कता ऐप से चयनित सड़कें शामिल हैं।

जियो- इंवेंट्री का आधा कार्य पूर्ण- निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 33 हजार 655 सड़कों में से 17 हजार 437 सड़कों की जियो इंवेंट्री का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही 9 जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रतलाम, जबलपुर, आगर-मालवा, मंदसौर और पन्ना जिले इस कार्य में अग्रणी हैं।

सिपरी सॉफ्टवेयर का उपयोग स्थल चयन में- सुगम संपर्कता परियोजना के तहत 2 गांवों, ग्राम पंचायतों, मजरों-टोलों और विद्यार्थियों के हित में सांदीपनि विद्यालयों तक बनने वाली सड़कों के लिए स्थान का चयन सिपरी सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। सड़कों की डीपीआर तैयार करने के लिए भी इस सॉफ्टवेयर और रिम्स पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। नई प्रस्तावित सड़कों का सर्वे में भी तकनीक उपयोग में लाई जा रही है। सर्वे की गई सड़कों में कार्य स्थल के हिसाब से सड़क निर्माण का प्राक्कलन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है।

जिला स्तर पर बनेंगे प्रस्ताव, स्वीकृत भी होंगे

परियोजना अंतर्गत प्रदेश में 7 हजार 135 नवीन सड़कों का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। प्रदेश के 29 जिलों में 1771 नवीन सड़कों का प्रस्ताव जिला स्तर पर स्वीकृत किया जा चुका है। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी अमले को तकनीकी बारीकियों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसमें राज्य स्तर से 2100 से अधिक तकनीकी स्टॉफ और विभिन्न श्रेणी के अभियंताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को भी निर्माण के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। परियोजना अंतर्गत बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता की जानकारी ड्रोन तकनीक से प्राप्त करने के अलावा सड़कों के निर्माण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की निगरानी जनपद, जिला और राज्य स्तर पर डैशबोर्ड से करने की पहल की गई है।

एक चेहरे पर 246 सिम, साइबर क्राइम का खुलासा

एआई से खुली पोल, दो गिरफ्तार

आधार की फोटो कॉपी कर करते थे इस्तेमाल

भोपाल (नप्र)। भोपाल में साइबर क्राइम ब्रांच ने बड़े फर्जी सिम रैकेट का खुलासा करते हुए दो पीओएस एजेंटों को मंगलवार गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक ही व्यक्ति के चेहरे का उपयोग कर करीब 246 फर्जी सिम कार्ड जारी किए।

इन सिम कार्ड्स को अलग-अलग नाम और पतों पर एक्टिवेट किया गया, जिससे इनके साइबर अपराधों में इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। मामले का खुलासा ऑपरेशन फेस के तहत की गई कार्रवाई में हुआ, जो फर्जी सिम नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए चलाया जा रहा है।

एआई से खुली पोल

एआई तकनीक ने फर्जी सिम एक्टिवेशन के बड़े नेटवर्क की पोल खोल दी। इस कार्रवाई की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा 2023 में एआई आधारित फेसियल रिकग्निशन टूल के जरिए संदिग्ध मोबाइल सिम धारकों का डाटा उपलब्ध कराए जाने से हुई। इस डाटा में ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें एक ही व्यक्ति के चेहरे का उपयोग कर अलग-अलग नाम और पतों पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड एक्टिव पाए गए। इसी इनपुट के आधार पर भोपाल में सक्रिय फर्जी सिम रैकेट का खुलासा हुआ।

- **तकनीकी विश्लेषण से पकड़े गए आरोपी-** पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और डेटा एनालिसिस के आधार पर जहांगीराबाद निवासी देवेंद्र यादव और इतवारा क्षेत्र निवासी सैफ कुरैशी को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपी पीओएस एजेंट के रूप में काम करते थे और सिम बेचने के बदले मिलने वाले इनाम के लालच में इस अवैध गतिविधि में शामिल हुए।
- **अन्य साथियों की तलाश जारी-** पूछताछ में आरोपियों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने की बात कबूल की है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इन फर्जी सिम कार्ड्स का उपयोग किन-किन साइबर अपराधों में किया गया।
- **ऐसे रखें सावधानी-** पुलिस ने आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सिम जारी कराते समय यदि विक्रेता बार-बार प्रक्रिया दोहराने को कहे तो सावधान रहें। अपने आधार कार्ड पर जारी सिम की संख्या की जानकारी दूरसंचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ली जा सकती है। साइबर अपराध की किसी भी घटना की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 या भोपाल साइबर क्राइम के नंबर 9479990636 पर दी जा सकती है।

फर्जी दस्तावेजों से सिम एक्टिवेशन का खेल

जांच में सामने आया कि आरोपी ग्राहकों के आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी अपने पास रख लेते थे और उन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अलग-अलग नामों से सिम जारी करते थे। एक ही व्यक्ति की फोटो लगाकर करीब 250 सिम एक्टिवेट की गईं। आरोपियों ने यह काम कमीशन और कंपनी के इंसेंटिव के लालच में किया।

साइबर क्राइम के मुताबिक, 2023 में दूरसंचार विभाग द्वारा एआई आधारित फेसियल रिकग्निशन टूल के जरिए ऐसे संदिग्ध कनेक्शनों की पहचान की गई थी, जिनमें एक ही चेहरे पर 50 से अधिक सिम सक्रिय पाए गए। इसी इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए भोपाल में यह गिरफ्तारी की गई।

राजभवन के सामने पाइप लाइन फूटी, अचानक धंस गई सड़क

सामने भराया पानी, जर्जर हिस्से से ही गुजरी विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में लोक भवन (राज भवन) के ठीक सामने सड़क धंस गई। इसके नीचे पानी की लाइन गुजरी है। ऐसे में लीकेज होते ही सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, जिस समय सड़क धंसी तब वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना मंगलवार डेढ़ बजे की है। लोक भवन के सामने से घाटी से बड़ा तालाब के बिना फिल्टर वाले पानी की पाइप लाइन गुजरी है, जो अचानक फूट गई। इससे पानी की धार बह निकली। नीचे पीएचक्यू के पीछे की सड़क का डेढ़ सौ मीटर का हिस्सा तालाब में तब्दील हो गया। यहां एक फीट तक पानी भर गया।

जर्जर हिस्से से ही गुजरी विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी

सड़क धंसने और पाइप लाइन फूटने के बावजूद ट्रैफिक डायवर्ड नहीं किया गया। इस दौरान गाड़ियां गुजरती रही। कई गाड़ी जर्जर हिस्से के ऊपर से ही गुजर गई। इस दौरान बड़ा हादसा होने से बच गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला भी यहां से गुजरा।

सड़क पर पत्थर-गिट्टी जमा, कई लोग गिरे

पानी की धार इतनी तेज थी कि घाटी के एक तरफ के मलबे को भी अपने साथ बहा ले गए। इससे सड़क पर पत्थर और गिट्टी जमा हो गई। इस कारण सड़क से गुजरने वाले कई लोग या तो गिर गए,या गिरने से बच गए।

'तीन तलाक' पर रिसर्च करने आई कन्नड़ लेखिका से मारपीट की गई

डेढ़ महीने बाद भी शिकायत दर्ज नहीं, पुलिस पर सवाल उठे

इंदौर। करीब डेढ़ महीने पहले हुई एक गंभीर घटना अब नया मोड़ लेती नजर आ रही है। कर्नाटक की एक महिला लेखिका, जो ऐतिहासिक कानूनी मामले पर किताब लिखने के लिए शहर आई थीं, कथित तौर पर भीड़ की हिंसा का शिकार हो गईं। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिससे पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

घटना 15 फरवरी की बताई जा रही है, जब खजराना थाना क्षेत्र की सिकंदराबाद कॉलोनी में लेखिका परवीन को भीड़ ने घेर लिया। उनके मुताबिक, उन पर बच्चा चोरी का झूठा आरोप लगाकर सरेआम मारपीट की गई और उनके साथ अभद्रता भी हुई।

लेखिका का आरोप है कि जब मामला थाने पहुंचा, तो वहां एफआईआर दर्ज करने के बजाय उन पर समझौते का दबाव बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में उनसे जबरन माफीनामा लिखवाया गया और उनके मोबाइल से घटना से जुड़े वीडियो भी डिलीट करवा दिए गए। इसके बाद उन्हें बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया और वे अगले ही दिन कर्नाटक लौट गईं।

25 लाख की मांग से विवाद

परवीन के अनुसार, पूरा विवाद उनकी रिसर्च से जुड़ा है। उन्होंने नवंबर 2025 में एक चर्चित कानूनी मामले पर किताब लिखने की योजना बनाई थी और इसी सिलसिले में संबंधित परिवार से संपर्क किया। इंदौर आने के बाद जब उन्होंने मुलाकात की, तो कथित तौर पर उनसे जानकारी के बदले 25 लाख रुपये की मांग की गई। बाद में उन्हें किताब के मुनाफे में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला एक अनुबंध भेजा गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था।

नए अनुबंध और हिंसा का आरोप

लेखिका का कहना है कि 15 फरवरी को रिकॉर्डिंग के बाद उन पर एक नया अनुबंध साइन करने का दबाव बनाया गया, जिसकी शर्तें पहले से अलग थीं। इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि जब वह वहां से निकल रही थीं, तो उन्हें पकड़कर बच्चा चोर बताकर भीड़ को उकसाया गया।

पुलिस पर रिश्वत का आरोप

परवीन ने यह भी आरोप लगाया कि थाने में एक पुलिसकर्मी ने उनके मोबाइल जब्त किए और समझौते के नाम पर 2 लाख रुपये की मांग की। फिलहाल, वे कर्नाटक से ही ऑनलाइन माध्यमों के जरिए शिकायत दर्ज कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं।

पुलिस का पक्ष

खजराना थाना प्रभारी का कहना है कि उस समय दोनों पक्ष कार्रवाई नहीं चाहते थे। पुलिस ने रोजनामचा में एंट्री की थी और महिला अधिकारी द्वारा बयान भी रिकॉर्ड किए गए थे। उनके मुताबिक, लेखिका ने खुद ही एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया था।